साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 7 अंक 31 प्रति सोमवार इंदौर, 11 से 17 मार्च 2013 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

मोदी की छवि और अपने कुकर्मों को दबाने-कांडों की श्रृंखला

जनता व मीडिया का ध्यान बंटाने कांग्रेस ने रचे क्रमिक षड्यंत्र

बलात्कार, सैनिकों की गर्दन उड़वाना, अफजल की फांसी, कुंभ में भगदड़, आतंकी हमला, पेट्रोल कीमतें बढ़ाना, सब एक पिपासु कांग्रेसी धूर्तों के षड्यंत्र

केन्द्र की सत्ता के शीर्ष पर बैठे कठपुतली प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन यथार्थ में धूर्त, मक्कारी, चालाकियों, जालसाजियों का भी सरदार है, इसकी सत्यता इस राष्ट्र की 125 करोड़ जनता तो जानती ही हैं, वरन् विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो भारत के बारे में जानने समझने की क्षमता रखते हैं, वे इस तथ्य को भलीभांति जानते हैं। वर्तमान में गांधी खानदान के कुंवर की ताजपोशी के लिये उसकी अम्मा सोनिया के साथ ही उनके सिपाहसालारों का धूर्त गिरोह भी उसकी प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिये उतावला है, जिसका सीधा मुकाबला गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर विराजे गुजरात के मोदी से है।

मोदी की लोकप्रियता का आलम ये है कि उससे चिढ़ने और जलने वाली क्योंकि भाजपा का नेता होने के साथ ही उसके बेटे राहुल का

सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा है, उसकी छवि से डकैत कांग्रेसियों के साथ ही पूरी संप्रग गिरोह के सारे कानूनी प्रयासों से ताकि तो गोधरा दंगों में लपेटे में आ जाये, जो कि उसके घोर राजनैतिक विरोध का परिचायक तो है ही वरन उसके विरोध में उसकी ही भाजपा के भी सैकड़ों दिग्गज, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, म.प्र. का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तक भी हैं। इसलिये भाजपा के ही कुछ दिग्गज जो दिल्ली में विराजते हैं, मोदी की छवि बर्बाद करने, उसकी लोकप्रियता घटाने और मोदी का नाम मीडिया में न छा जाये और हमारी लोकप्रियता और प्र.मं. पद की दावेदारी न समाप्त हो जाये, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर उसकी हां में हां करने लगे, उस भाजपा के दिग्गजों का साथ पाकर कांग्रेस ने कम से मोदी की जीत के विरुद्ध उसकी मीडिया और जनता के मस्तिष्क से छवि धोने और भुलाने के लिये क्रम से घोर शर्मनाक कांड करवाये, जिसमें 16 दिसम्बर 12 के बलात्कार कांड को इतना न केवल तूल दिया, फेसबुक पर धन देकर युवाओं का आक्रोश भड़काया इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रकों से पत्थर-ईंटे डलवायी गई और बाकायदा युवाओं को आमंत्रित कर दंगा भड़काकर पथराव करवाया गया, **(शेष पेज 7 पर)**

पूंजीवाद ले डूबा अमेरिका, भारत को भी गुलाम और भिखारियों का देश बनायेंगे फिर

अमेरिका कंगाल - 2.70 लाख कर्मचारियों की नौकरी समाप्त

पूंजीपति हर कार्य लाभ के लिये करता है, युद्ध हो या दान, जहां लाभ नहीं, वहां कोई काम नहीं, कर्मचारी भूखें मरे या देश डूबे

वाशिंगटन के व्हाइट हाऊस में पुनः गद्दी संभालने वाले ओबामा ने विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका को बद से बदतर बना दिया। पहली बार राष्ट्रपति बनने के 208-09 में 150 से ज्यादा बैंकों ने अपना दिवाला घोषित करते ही सिद्ध कर दिया था कि ओबामा अमेरिकी इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली राष्ट्रपति हैं, जो सत्ता संभालने, नियंत्रण में लाने की अपेक्षा हिलेरी क्लिंटन से रोमांस में ज्यादा व्यस्त दिखा। दूसरी बार सत्ता संभालते ही आर्थिक संकटों और बेरोजगारी से त्रस्त अमेरिकी जनता को 2.7 लाख कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को जो तोहफा दिया, उससे सिद्ध हो गया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, इसके परिणाम जैसा कि समय माया ने लिखा था कि सारे अमेरिकी राज्य अपनी

स्वतंत्र सत्ता कायम कर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सत्ता चलाने को तैयार हैं। जो शीघ्र ही संपन्न होगा भविष्य में, इसके पीछे के कारणों को जाने तो इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है, जहां सारी अर्थव्यवस्था की बागडोर बड़े-बड़े पूंजीपति कंपनियों, कार्पोरेशन के हाथ में रहती हैं, वहां पर रेल्वेज, एयरवेज से लेकर जलापूर्ति तक की व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में हैं, जैसे हमारे राष्ट्र में अंबानी और टाटा सरकार चलाते और हांकते हैं वैसे ही वहां बड़े-बड़े हथियार उत्पादक, कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर जैसे माइक्रोसाफ्ट, तेल उत्पादक, विद्युत उत्पादक और वितरण कं. न केवल सरकार चलाती हैं। वरन सरकारों की विदेश नीति व्यावसायिक, युद्ध आदि को भी निर्देशित करती है। स्वाभाविक है हर पूंजीपति हर कार्य में पहले अपना लाभ देखता हैं, कि कितने बड़े विनियोजन से भविष्य में कितना लाभ होगा, जैसे कि ईराक में इन तेल कं. ने जो युद्ध थोपा, उसका उद्देश्य कहीं से भी रासायनिक और परमाणु हथियारों को पकड़ना और रोकना नहीं था उनका उद्देश्य कहीं से भी रासायनिक और परमाणु हथियारों को पकड़ना और रोकना नहीं था।

(शेष पेज 8 पर)

आंकड़ों की बाजीगारी-नोट और वोट बैंक मजबूत करने

चीटांबर बजट नौटंकी 13-14 जनशोषक पूंजीपति पोषक

बहुराष्ट्र कं. को लाभ पहुंचाकर मोटा कमीशन डकारने, रियायतों की झूठ का पुलिंदा थमाकर वोट बटोरने की चुनावी नौटंकी

केंद्र में बैठी कांग्रेस और संप्रग गिरोह के महाधूर्त, जालसाज चीटअंबरम का इतिहास रहा है कि वह लाखों करोड़ रु. का कमीशन बहुराष्ट्रीय कं. से बटोरने के लिए उनके इशारे पर राष्ट्र के संसाधनों को बेचने, गिरवी करने, जनता का चहुंदी शोषण करने और जालसाज धूर्तों के राष्ट्रीय यथा अंबानी, टाटा, बिरला आदि बहुराष्ट्रीय कं. यथा आई,टी.सी., हिन्दुस्तान बनाम युनीलीवर, केडबरीज पेप्सीको, कोका कोला, पारले, मेक्डावल आदि को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था के दृष्टिकोण से आंकड़ों की बाजीगारी दिखाकर जनता, मीडिया को भ्रमित करने का खेल खेलता रहा हैं, वर्तमान वर्ष में 7 राज्यों में विधानसभा के अगले वर्ष में लोकसभा के चुनावों के दृष्टिकोण से बजट नौटंकी की

13-14 बनाम चीटांबर बजट नौटंकी 13-14 मूल रूप से इन हरामखोर सत्ताधीशों के लिये नोट और वोट की कमाई के लिये प्रस्तुत की गई है। कुछ विषैले सत्य देखें

मनरेगा रु. 33000 करोड़ :- ग्रामीणों, खेतीहर मजदूरों को सीमांत कृषकों, लघुजोत और मध्यम जोत अर्थात 25-50 एकड़ कृषि भूमि पर उन्हें खेतीहर मजदूर उपलब्ध न हो सकें, ताकि वो मजदूरों के अभाव में कृषि कार्य न कर सकें और करें तो भारी घाटे में फंसकर या तो आत्महत्या करें या कृषि भूमि बहुराष्ट्रीय कं. को बेच दें या पट्टे पर सौंप दें, दूसरी ओर सरपंचों, जनपद अध्यक्षों से लेकर मु.का.अ. जिला पंचायतों को 50 से 70% भ्रष्टाचार करने का मौका मिले, वो लूटपाट कर सकें और सरकार बनाम बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर नाचने के लिये बाध्य किये जा सकें, कृषि लागत बढ़े, जनता का शोषण किया जा सके।

युवाओं को प्रशिक्षण के लिये रु. 1000 करोड़ - ताकि बहुराष्ट्रीय कं. को उनके अनुसार प्रशिक्षित बंधुआ भारतीय मजदूर मिल सकें जो 10 से 14 घंटे जानवरों की तरह सिर झुकाकर काम कर सके,

(शेष पेज 6 पर)

लोकलुभावन, वोट-पावन, धन-आवन, बजट गायन- 2013

आंकड़ों की बाजीगरी, धन हड़पने, जन-मन बहकाने की

यदि सत्ता में नहीं भी आये, तो भी हजारों करोड़ की कमाई की व्यवस्था

म.प्र. सरकार के वित्तमंत्री राघवजी, जाति और पेशे से वित्तीय आंकड़ों के बाजीगर ने अपना प्रदेश का वित्तमंत्री रहते हुए 10वां म.प्र. सरकार का जो बजट पेश किया है, अधिकांश समाचार पत्रों ने अपनी समझ की पहुंच के आधार पर और नेताओं के मुखारबिंद से टपके शब्दों की व्याख्या को प्रकाशित किया है। जबकि हर बजट में सत्ताधीश हर आंकड़े, धन के प्रावधान से अपनी कमाई की व्यवस्था देखता है, चाहे तो केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें, धन कैसे प्राप्त किया जाये और अपनी अपनी सरकार में बैठे अपनों की कमाई की व्यवस्था कैसे की जाये, जन कल्याण के नाम स्वकल्याण हो।

विद्युत के लिये 13-14 में रु. 8856 करोड़ इसका 90% पैसा मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव और कंपनियों में

बैठे धूर्त प्रबंध संचालकों के रूप में इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी बिजली खरीदी में 1 रु. यूनिट की बिजली रु. 2 से 4 में खरीदी करेंगे, जबकि जनता से लगातार बिजली की कीमतों में 1993-94 से अभी तक हर वर्ष 2-3 बार बढ़ाया जाता रहा हैं, जो बिजली खरीदी जायेगी उसका भुगतान 90% उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व से ही किया जायेगा, यह प्रावधानित पैसा विद्युत कं. के एमडी अरबों रु. के झूठे खरीदी, रख-रखाव के नाम पी जाते हैं। जैसा कि समय माया वर्षों से प्रकाशित करता आ रहा हैं कि हजारों करोड़ रु. हर वर्ष बिजली कं के एमडी पी जाते हैं। विभिन्न जांचों में यह सिद्ध भी हो चुका है।

सड़कों के लिये रु. 4970 करोड़ बकवास है यह आंकड़ा 5593 कि.मी. सड़कें केवल कागजों पर बनाई जाकर पैसा हजम किया जायेगा, ग्रामीण सड़कों में 60,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण केन्द्र के धन से ग्रामीण सड़क में बताया जा चुका है। 2001 से सन् 2012 तक 1000 की आबादी के अधिकांश गांव बारह मासी सड़कों से मुख्य राज्य व राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ दिये गये हैं। अधिकांश राज्य मार्गों पर म.प्र. सड़क डकैत निगम ने बीओटी के अंतर्गत बनाकर टोलटैक्स से वसूली करवा रही है।

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सत्ताधीश पूंजीपति राक्षसों का गठजोड़

विश्व में पूंजीवादी राक्षसों द्वारा जनता के घोर शोषण ने ही चीन और रूस के साम्य तार को जन्म दिया था, रूस के लेनिनवादी, साम्यवाद और चीन माओवादी साम्यवाद ने उस घोर शोषित मजदूरों को समानता का अधिकार में पहले रोटी, कपड़ा और मकान के साथ मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का सरकारी प्रबंध था जहां पूंजीवाद का पूर्ण सफाया कर दिया गया था। 20वीं शताब्दी दूसरे दशक की इस मजदूर क्रांति की लहर का असर विश्व के कई देशों पर पड़ा, मजदूर आंदोलन ने दुनिया के कई राष्ट्रों की सरकारें इस साम्यवाद के अधीन आ गई, जो कि यूरोपीय राष्ट्रों के जालसाज पूंजीपतियों के गले नहीं उतरीं, जिसमें अमेरिकी पूंजीपति प्रमुख थे हालात यहां तक बने कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों का पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्रों में ध्रुवीकरण हो गया, पूंजीवादी राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका कर रहा था तो साम्यवादी राष्ट्रों की अगुवाई सोवियत रूस कर रहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होते-होते भारत में भी जब सेनाओं मुख्य रूप से भारत की जलसेना में जब बगावत हुई, तो अंग्रेज घबरा उठे, क्योंकि उसका असर सीधे थलसेना जिसके दम पर अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, में बगावती तेवरों के देखते हुए भारत को आजाद करने के लिये विवश हो गये, आजादी के बाद हमारे राष्ट्र के नेताओं ने दुनिया में पूंजीवाद और साम्यवाद के ध्रुवीकरण को देखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था से राष्ट्र को संचालित करने की व्यवस्था की ताकि भारत की जनता का कुछ गिने-चुने पूंजीपति उद्योग कराने शोषण न कर सके और बड़े व भारी पूंजी निवेश के खास सेवाओं यथा संचार, डाक-तार, रेलवे, बिजली, यातायात, सड़कें आदि सरकारी क्षेत्रों में रखे गये, जिससे राष्ट्र ने प्रगति करते हुए इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया। इसके विपरीत अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ ही विश्व के सभी राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त शैतान संघ जिसे यूरोपीय पूंजीपतियों के इशारे पर हांका जा रहा था ने विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से पहले राष्ट्रों को उनके विकास के नाम धन देना, उस धन का उपयोग उस राष्ट्र के प्रशासकों को भ्रष्ट बनाने और धन को हजम करने के बाद उस कर्ज की वापिसी की शर्तों में उस राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर हांकने और लाभ कमाने में किया जाने लगा। इस प्रकार पूंजीपतियों की संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त यूरोपीय शैतान संघ की विकास के लिये विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के धन बांटकर साम्यवादी राष्ट्रों यथा रूस और चीन में अपना व्यवसाय जाल बिछाकर लाभ कमाने और जनता के शोषण का कुत्सित प्रयासरत रहा, अब रूस और चीन की धरती पर भी पूंजीपति धूर्त उद्योगपतियों न केवल उद्योग लगाये वरन् वहां के प्रशासन तंत्र में भी भ्रष्टाचार कर जनता का शोषण शुरू कर दिया। पूंजीपति मुद्रा राक्षस अपने धन के बदले सत्ताधीशों को धन देकर अपना गुलाम बनाकर कानून बनवाने से लेकर सत्ता को अपनी तरह से हांक कर जनता का घोषण करता है, अपने फायदे के लिये न केवल वरन् सारा बजट, नीतियां आदि तक बनवाता है। जैसा कि हमारे राष्ट्र की धूर्त कांग्रेसियों की सत्ता अंबानी, टाटा, बिरला, भारती आदि के लिये कर रही और करती रहेगी, विदेशी निवेश की छूट देकर फुटकर व्यवसाय, बैंकिंग, बीमा व्यवसाय में 49% तक की छूट देकर इस राष्ट्र की 125 करोड़ जनता का न केवल शोषण करवाने के न केवल रास्ते वरन् ईस्ट इंडिया कं. की तरह इन कंपनियों को बुलाकर पूरे राष्ट्र को गुलाम बनाने की राह पर निकल पड़ी है, बदले में हराम का मोटा पैसा कमीशन के रूप में हजम भी कर रही है।

मुद्रा राक्षस की सेवा में पूंजीपति और सत्ताधीशों ने मिलकर राष्ट्र की जनता को बेरोजगार बनाकर उनके उद्योग धंधे छीनने, उनको गुलाम व बंधुआ मजदूरों को मजदूरी के बदले अनाज आदि की व्यवस्था शुरू करवा दी। पेक्ड खाद्य, आधार कार्ड को बनवाना और उसको अनिवार्य बनाकर जनता के रहन-सहन, खाना-पीना, जीवन स्तर, आना-जाना, लेन-देन सब जानकारी एकत्रित कर बहुराष्ट्रीय कंपनी को उपलब्ध करवाने का षड्यंत्र इसी पूंजीवादी और सत्ताधीश राक्षसों के गठजोड़ कर जनता के शोषण का हिस्सा हैं, पर इस लोकतंत्र में चुने गये गण, लूट तंत्र का हिस्सा बन और विपक्ष में बैठ केवल कमाई के लिये ही एक सुर में अलाप कर राक्षसों की तरह शोषण में जुटे हैं।

आंकड़ों की बाजीगरी, धन हड़पने, जन-मन बहकाने की

पेज 1 का शेष

500 या अधिक पर 1000 से कम की आबादी के गांवों को मु.मं. सड़क विकास योजना में और ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जोड़ रहा है। रु. 90 लाख प्रति कि.मी. में सड़कें म.प्र. लो.नि.वि. भी नहीं बनाता, अर्थात पैसा हजम करने के लिये। सिंचाई के लिये रु. 4675 करोड़- यह बजट जिस विभाग जल संसाधन को दिया जाना है, वहां बैठे अधिकांश उच्च पदों पर बैठे कोटे के इंजीनियरों को बाबू और उपयंत्री हांकते हैं। जो काम के हैं। उन्हें अलग-थलग 30-35 वर्षों से एक ही पद पर सड़ाया जा रहा है। फिर जो काम कर रहे हैं, उन्हें खाने-कमाने, लूटने और लुटाने से मतलब है, काम से नहीं, फिर पुरानी योजनाओं में जो अरबों रु. लगा हैं, उनके कार्यों की समीक्षा ही कर लो फिर प्र.स. जुलानिया ने सुधारा है, पर अधिकांश पैसा हजम कर लिया जायेगा।

पेयजल के लिए रु. 1743 करोड़

जब मु.मं., लो.स्वा.यां.मंत्री जो शं बिसेन प्रधान सचिव एस.के. मिश्रा ने जल निगम बना ही दिया है, अधिकांश ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों में नल-जल योजना चल ही रही है, बड़ी योजनाओं में 75% धन केन्द्र सरकार से आ ही जाता हैं, तो इससे क्या भ्रष्ट प्रमुख अभियंता सेहरा से लेकर मु.अभियंताओं को पाइप, मोटरों की खरीदी से का. यंत्रीयों से लेकर उपयंत्रियों तक सबको धन हड़पना ही है। इसमें से भी रु. 743 करोड़ का कार्य और 1000 रु. करोड़ हजम किये जायेंगे।

ग्रामीण विभाग के लिये रु. 7444 करोड़ - ग्रामीण विकास के नाम पर जगजाहिर है क्या हो रहा है, बेशक यह पैसा सरपंचों से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक सब बंदरबांट करेंगे, पूरा पैसा कागजों पर हजम करने का मौका देकर वोट बटोरे जायेंगे गांवों से, जिसमें ग्राम पंचायतों से चलकर मु.का.अ. जनपद पंचायतों और मु.का.अ. जिला पंचायतों तक जो लूट चारों तरफ मची है। सारा पैसा लूट और भ्रष्ट्राचार में समाप्त हो जायेगा, इंदिरा और मुख्यमंत्री आवास योजना में खर्च किये धन का पूर्व में कैसा कागजों पर उपयोग होकर आवासों का निर्माण किया गया है, म.प्र. के किसी भी गांव के भ्रमण से जाना जा सकता है।

महिला बाल विकास रु. 5163 करोड़ - इस बजट का 95% पैसा वहां बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से लेकर आईसीडीएस अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारियों से लेकर आयुक्त/संचालक, सचिव, प्रधान सचिव और मंत्री रंजना बघेल मिलकर डकार जायेंगे। कुपोषण के शिकार प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा गरीब और ग्रामीण बच्चों के नाम अवश्य आंगनवाड़ियों की उपस्थिति पंजी भर में शोभा बढ़ाते हैं। 25% आंगनवाड़ियों में कोई भी बच्चा और महिलायें नहीं आतीं, 50% में उपस्थिति यंत्री में दर्ज बच्चों और महिलाओं में से मात्र 10% ही उपस्थिति औसतन 25% आंगनवाड़ियों में तो कई-कई दिनों तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ताले तक नहीं खुलते। यह रिपोर्ट संयुक्त संचालक उज्जैन से सूचना अधिकार में प्राप्त जानकारियों का निष्कर्ष है।

अजा एवं अजजा कल्याण के लिये रु. 11797 करोड़ - इस मद का 90% पैसा आजादी के बाद से अभी तक जिलों में बैठे सहायक आयुक्त से लेकर वहां बैठे बाबु तक अरबों रु. झूठे व्हाउचरों और कागजी खानापूर्ति से हजम कर जाते हैं। जिसका पैसा मंत्री तक पहुंचता है, जहां बाबु स्तर का कर्मचारी भी रु. 25-50 लाख तक खर्च कर देते हैं। छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, लेखन सामग्री, छात्रावासों के खर्च के नाम पर करोड़ों रु. हजमकर लेते हैं। यह चुनावी वर्ष है, इसलिए 20-25% पैसा यथार्थ में खर्च कर ही दें।

शिक्षा के लिये 13663 करोड़ - शिक्षा का जब पूर्णतः व्यवसायीकरण कर निजी हाथों में दिया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में 80% शिक्षा निजी क्षेत्रों में और गांवों की 10000 से ज्यादा आबादी में 50% निजी क्षेत्रों में दी जाती है, गांवों में स्कूलों के निर्माण, पेयजल आदि की व्यवस्था केन्द्र सरकार के धन से की जा रही है, संविदा शिक्षकों को बंधुआ मजदूरों की तरह भुगतान किया जाता है। बेशक म.प्र. की जालसाज शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक जरूर उल्टी सीधी खरीदी के अरबों रु. के झूठे व्हाउचरों से व अन्य तरीके से स्कूलों के आवंटन के नाम पर जरूर वसूली करेंगे।

स्वास्थ्य के लिये रु. 4147 करोड़ - केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिसमें एनआरएचएम, आरसीएच व अन्य योजनाओं में 3000 रु. करोड़ से ज्यादा का बजट किया जाता है। जिसका 50%, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जिलों में मु.चि.अ. तक जीम जायेंगे। पुलिस बल के लिये रु. 3962 करोड़-आधे से ज्यादा बजट वेतन में ही पूरा हो जायेगा पर रु. 1962 करोड़ के धन का जो उपयोग संचालन में किया जायेगा, उसका 50% पैसा गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता से लेकर डीजी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और थाने के टीआई तक रखरखाव के नाम पर पी लिया जायेगा। बजट आंकड़ों की बाजीगरी मात्र अक्टू. 13 तक के लिये हैं, अर्थात यह मात्र 5-6 महीनों में खर्च और आय के आंकड़े हैं। क्योंकि नव. 13 में चुनाव होना हैं, 3 माह पूर्व से चुनावी आचार संहिता लगा दी जायेगी, अर्थात जून तक जो नया कार्य प्रारंभ हो गया तो ठीक अन्यथा अगली सरकार के पाले में।

आमजन को गैस पर दी गई 20/- प्रति टंकी राहत जबकि वर्ष मात्र 9 टंकियां मिलेंगी, कुल रु. 180/- ऊंट के मुंह में जीरा होंगी, इस बजट के प्रावधानों का मूल्य उद्देश्य जनता के कल्याण के नाम पर स्व कल्याण से धन बटोरना ज्यादा है, अगली सरकार में ये भाजपा आई न आई विधायक का टिकट मिला नहीं मिला, मंत्री बने मलाई खाना तो दूर सड़कों पर चप्पल चटकाते घूमेंगे नेताजी, सारी सुख-सुविधायें छीन जायेंगी, इस लिये हाथों से बटोरने का जमाना गया अब डंपरों से बटोरकर भर के जाने और कानोंकान खबर न हो सारे लेन-देन आनलाइन करके हजम करो वरना आगे बची हुई जिंदगी का क्या होगा, 7-8 महीनों की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रातें ही हैं। इसलिये जनकल्याणकारी बजट से जितना स्वकल्याण हो जाये बेहतर हैं।

अरबों की वसूली के लिये टर्न की अधिकतम असफल

म.प्र. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यथार्थ में भ्रष्टाचार की खान बन चुका है। 1970 से प्रारंभ इस प्राधिकरण की सभी योजनाओं को सन् 2000 तक पूरा हो जाना चाहिये था, परन्तु 1970 में सैकड़ों करोड़ की प्राधिकरण के सभी बांधों और नहरों की कीमत लाखों करोड़ में परिवर्तित हो गई, लाखों हेक्टेयर वन भूमि और कृषि भूमि बांध और नहरों में, बर्बाद करने, लाखों कृषकों की कृषि और निवासों को डुबोने के पीछे यथार्थ में 1980 से 2013 में सत्ता में रहे हर मुख्य नर्मदा घाटी मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य अभियांत्रिकीय और पुर्नवास से लेकर बांधों, नहरों के पुर्नवास स्थलों के विकास के उपयंत्रियों तक सबकों भ्रष्टाचार से धन बटोरने और वसूलने की स्वर्ण खान बना हुई है। इसके विपरीत एक कड़वा सच यह भी है कि पुर्नवास में नर्मदा घाटी- लोक निर्माण संभाग धरमपुरी में 12 उपयंत्री ऐसे भी हैं जो पिछले 25 वर्षों से उपयंत्री होने और उपयंत्रियों की तरह कार्यरत रहने के बाद अभी भी मस्टर पर दैनिक वेतन भोगियों की तरह इन हरामखोर मंत्रियों, पुर्नवास सदस्यों और उपाध्यक्षों की नीचता के चलते रु. 3500 से 4000/- वेतन पर ही उच्च न्यायालयों के आदेश के बाद भी दैनिक वेतन भोगियों के रूप में इस आशा से कार्य कर रहे हैं कि कल शायद नियमित कर दिये जाये, अर्थात इस प्राधिकरण में सबसे ज्यादा लूट और नीचता की पराकाष्ठा है।

यदि न.घा.वि.प्रा. के सभी निर्माण कार्यों, टेंडर प्रक्रिया, डिजाइन और वास्तविक निर्माण की जांच की जाये तो कदम-कदम हजारों घोटालों का परत दर परत खोलकर लोकायुक्त के हवाले करने पर न केवल सदस्य इंजीनियरिंग, पुर्नवास विद्युत उत्पादन, वन, पर्यावरण से लेकर अभी तक कार्यरत रहे सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से लेकर सारे इंजीनियर और बाबुओं तक सब लपेटे में आयेंगे।

'समय माया' के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के संबंध में

घोषणा पत्र

फार्म-4 (नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशक का स्थान	: इंदौर
2. प्रकाशन अवधि	: साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299, अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299, अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
5. प्रधान संपादक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299, अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों :	: नहीं

मैं **अजमेरा एस.पी. कुमार** एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 06 मार्च 2013

हस्ताक्षर
अजमेरा एस.पी. कुमार
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

मजाक बना दिया हरामखोर, धूर्त, महाभ्रष्ट डकैतों ने

लगातार किया जा रहा सूचना अधिकार अधि. का बलात्कार

वास्तविक अधि. और उसकी पारदर्शिता की आत्मा को हर दिन नये-नये मनचाहे संशोधन जिसके कार्यालय की सूचना मांगों, उसे ही धूर्त मक्कारों, शूकरों की आईएएस फौज ने बना दिया अपीलीय अधिकारी, क्यों देगा कोई अधिकारी अपने कुकर्मों की फोटोकॉपी, फिर अपीलीय भी तो वही हैं, कहां जायेगा आवेदक, सूचना आयोग में तो आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं की गई है। थक हारकर सिर पीट कर चुप हो जायेगा, जैसे लूटना हो वैसे लूटो, सब अपने बाप की जागीर हैं, काहे का लोकायुक्त आ.अ. सीबीआई, सब मुखेरे श्वानों की फौज हैं, लूटो और लूटाओं।

केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. के अंतर्राष्ट्रीय दबावों और श्री अजमेरा जैसे जिद्दी धरती पकड़ लोगों की पारदर्शिता और जानकारी देने के वर्षों से चलाये जा रहे अभियान के सामने नतमस्तक हो और अपनी महानता दिखाने के लिये सूचना अधिकार अधि. 05 को 13/7/05 से लागू कर सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों को अधिनियम की मंशानुसार तैयार करने के लिये 120 दिन का समय देकर 12 अक्टू.05 से लागू करवा दिया गया, जब यह अधिनियम लागू किया गया था, केन्द्र शासन रु. 15 अरब से ज्यादा इस पर जनता का धन खर्च किया था, ताकि पूरे देश की राज्य सरकारों के व केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में इसके लिये रु. 2 से 5 लाख रु. खर्च के लिये देकर इसके लिये अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था करवाई गई थी।

कार्यालय प्रमुख को लोक सूचना अधिकारी हर जिला, तहसील ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये जाकर उनके वरिष्ठों को उनका अपीलीय अधिकारी नियमानुसार बनाया गया था, धारा 4 के अंतर्गत दिये गये 17 बिन्दुओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो वह भी मुफ्त में, इंटरनेट साइटों पर और उस कार्यालय के सूचना अधिकार कक्ष में, इस अधिनियम को लागू हुये 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी धारा 4 के 17 बिन्दुओं की जानकारी, जिसमें प्राप्त धन के उपयोग, कार्यपद्धति, कौन सा कर्मचारी, अधिकारी के नाम, पते, फोन व मोबाइल नं. के साथ उसकी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों के निर्वहन तक सब कुछ उपलब्ध करवाया जाना चाहिये था, अभी तक राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्र की केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 99% कार्यालयों ने यह जानकारी भी नहीं डाली, अर्थात रु. 15 अरब से ज्यादा की बर्बादी के बाद भी न केवल शासकीय कार्यालयों वरन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की इंटरनेट साइटों पर भी पूरी धारा 4 की जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके साथ ही 90% देश के जिला और सत्र न्यायालयों की साइटें ही नहीं बनाई जा सकी हैं। पुलिस थानों की साइटों पर शिकायत भेजने तक की सुविधायें तो दूर थानों की भी जानकारी भी नहीं है। यह हाल केवल म.प्र. का ही वरन् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूर, चेन्नई जैसे महानगरों का है, तो दूर दराज के इलाकों की कहानी और वास्तविकता तो समझी जा सकती है, थानों पर बैठे, मुंशी, हेड कांस्टेबल तो बिना लिये-दिये कोई शिकायत लिखना या प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने की जहमत कैसे उठा सकते हैं। 90% मामलों में शिकायत फाड़ कर फेंक देने के आदी हैं। यहां तक की हत्या, लूट, डकैती, जालसाजी और ठगी, चोरी, छेड़छाड़, बलात्कार, मारपीट, हत्या के प्रयास तक के मामलों में फरियादी न्यायालय में सीधी वकीलों के माध्यम से फरियाद कर आदेश करवाने के बावजूद एफआईआर तक नहीं लिखते, ताकि काम का बोझ न बढ़ जाये, अपराधों का रिकार्ड न बढ़े, ताकि टीआई उपनिरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों से लेकर हेड साब को और सभी पुलिस वालों को कहना मौका मिल सके कि हमारी सेवायें श्रेष्ठ हैं और सब शांति है।

अपराधी, सटोरिये, वारंटियों, गुंडे-बदमाशों, जेबकतरों, वैश्यावृत्ति करवाने वालों, वैश्यावृत्ति करने वालियों के काम धंधे चलते रहें और उनका लाखों रुपयों का महीना मिलता रहे, यदि ऑनलाइन रिपोर्ट लिखने और लिखवाने लगे तो थाना निरीक्षकों से लेकर एसपी, डीएसपी, सीएससी, आईजी, डीआईजी, डीजी सबका जीना मुश्किल हो जायेगा। फिर क्यों धारा 4 की जानकारी उपलब्ध करवाई जाये, जब पुलिस स्वयं ही कानूनों का बलात्कार सरकार के इशारे पर कर रही हो, तो सरकारों में बैठे नेता मंत्री अधिकारी, कर्मचारियों का तो परम कर्त्तव्य हैं कि जनता को भ्रमित, करो, लूटों और वसूली करो, यदि धारा 4 की जानकारी साइटों पर डाल दी गई, सूचना अधिकार कक्षों में मुफ्त में उपलब्ध करवा दी गई तो कोई भी चलता-भलता बुद्धिजीवी इनकी सच्चाइयों को जानकार इन्हें यथार्थ का आइना दिखा देगा,

सूचना के अधिकार अधि. 05, 14 अप्रैल 05 से लागू कर 3 माह का समय सभी केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को समझने, 13 जुलाई से 12 अक्टूबर तक उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया था, पर प्रदेश स्तर पर पहुंचते-पहुंचते ही इसका बलात्कार किये जाने लगे थे, केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन विभाग ने निरीक्षण और अवलोकन के लिये रु. 5/- प्रतिघंटा निर्धारित किये थे। वह पत्र म.प्र. में आते-आते यहां के जालसाज हरामखोरों ने उसे रु. 50/- बना दिया। फिर म.प्र. में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उसमें सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की दो साल से ज्यादा समय नियुक्ति ही नहीं की, जब उच्च न्यायालय में याचिका लगाई तब 3 अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त किये जो अपने काल में श्रेष्ठ विभागीय डकैत थे जिसमें एक था इकबाल अहमद और दूसरा था दिनेश सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक तीसरे थे पत्रकार महेश पांडेय जिन्हें अंत तक कोई काम ही नहीं दिया गया, ताकि वो सरकार की पोल न खोल दें। अभी तक उच्च न्याालय के नियुक्ति के आदेश के बाद भी मु.सू. आयुक्त, 4 आयुक्त और 8 आयुक्त संभागीय स्तरों पर म.प्र. में नियुक्त नहीं किये गये, जो महाभ्रष्ट हो, सरकारी अधिकारियों के सामने, आवेदकों की अपील को बलाये ताक रखकर टुकड़ा खाकर उनकी इच्छानुसार दुम हिलाते खड़े रहे। भाजपा की शिवराज सरकार को ऐसे राक्षस चाहिए जो शासकीय दानवों की फौज के भ्रष्टाचारों की रक्षा हेतु आंख मींचकर जनहितों को अपनी कुटिल चालों से कुचलते हुए कोई भी जानकारी और उसके दस्तावेजों को बाहर न जाने दें। पर ये सब तथ्य तो जब लागू होंगे, जब आवेदक द्वितीय और अंतिम अपील तक पहुंचेगा।

धूर्त मक्कार म.प्र. के मुख्य सचिव आर. परशुराम को मुख्यमंत्री शिवराज ने समय विस्तार ही उसके भ्रष्टाचारों, धूर्तता, मक्कारी पूर्ण कार्यों के लिये ही दिया है। इस धूर्त श्वास ने सूचना अधि. अधि. 05 का खूब बलात्कार किया। हर जिला अधिकारी को जो कि कानून में लोकसूचना अधिकारी बनाया गया था, इस परशुराम ने कृषि जिला पंचायतों, ग्रामीण विकास में उन्हें ही अपीलीय अधिकारी बना दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि जिला पंचायत अधिकारियों से जानकारी मांगों तो या तो देंगे ही नहीं, देंगे तो मांगों कुछ तो देंगे कुछ या आधी-अधूरी, इंदौर के मु.का.अ. गोपाल दांड से जानकारी मांगी गई, इस हरामखोर ने एनआईजीएस के पैसों से सड़कों के निर्माण में 70% से ज्यादा पैसा खर्चकर उसका 40% हजम कर लिया। फिर शिक्षकों की, एनआरएचएम, आरसीएच से लेकर जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्वयं की पंचायत व अन्य में संविदा नियुक्तियों में भी इस शूकर ने काफी पैसा जो करोड़ों में होता है। हजम किया गया, फिर उनकी संविदा बढ़ाने, हटाने के नाम से उपयंत्रियों, बाबुओं, लेखाकारों, कम्प्यूटर आपरेटरों आदि से सभी जालसाजीपूर्ण काम करवाना, काम कुछ डीपीआर कुछ, फिर 60% कुल धन का, मजदूरी में भुगतान होना चाहिये उसमें भी करोड़ों रु. हजम किये जाकर झूठे व्हाउचर लगाये गये, जिसकी जानकारी मांगने पर कुल आवंटन अलग-अलग मदों में कितना आया, के स्थान पर इंदिरा आवास योजना की 90 पेज की रिपोर्ट पकड़ा दी गई, जब अपील की गई तो शासन का आदेश दिखा दिया कि मेरी विरुद्ध अपील कलेक्टर नहीं मैं स्वयं सुनूंगा, 11/2/13 की उस अपील का अभी तक पता ही नहीं हैं, कहां गायब कर दी गई, इस मुख्य सचिव आर. परशुराम इस तरह की सैकड़ों जालसाजियां अपना हिस्सा डकारने के लिये प्रदेश के 100 से ज्यादा विभागों में की है।

भारत के जिस प्र.मं. मनमोहन ने इसे बनाया था, उस धूर्त मक्का ने भी इसका बलात्कार करते हुए इसकी पारदर्शिता की मूल आत्मा का गला घोंटते हुए जालसाजीपूर्ण तरीके सैकड़ों संशोधन करवा दिये। जैसे कानून, जनता का धन प्र.मं. मनमोहन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सभी विभागों के अधिकारियों के बाप की जागीर हों, उसे वो जैसे चाहे हजम करते रहे और उनसे कोई कुछ न बोलें, उसकी जानकारी न मांगे। सूचना का अधिकार अधि. 05 लागू हुये 8 वर्ष बीत गये, सत्ताधीश चाहे तो केन्द्र की कांग्रेस और उसके संप्रग गिरोह की हो या राज्यों में मुखेरे जानवर पार्टी, समाजवादी या अन्य किसी की भी सबका उद्देश्य धन बटोरना ही है, येन-केन प्रकरेण जनता के नाम स्वयं के बैंक खातों का भरना, 25 से 50% कार्य कागजों की खानापूर्ति कर पूरे कर लिये जाते हैं। फिर यदि उनकी आवेदक फोटोकापी मांगता हैं, तो जिस रोकड़ बही की फोटोकॉपी बाजार में दो रु. में होती है, उसकी फोटोकॉपी के लिये का.यं.लो.स्वा.यां. खंड यांत्रिकीय व उसके उपखंडों के सहा. यंत्रियों ने किसी हरामखोर ने रु. 24/- से लेकर रु. 28/- प्रति पेज मांगी जाती है। अपील में उनके आका मु.अ.लो.स्वा.यां.म.प्र. यांत्रिकीय उसे खारिज कर देता है। वैसे उनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं धरती पर।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सूचना के अधिकार में जानकारी भी केवल पत्रकारों और नेताओं के अतिरिक्त कोई मांगना भी पसंद नहीं करता वो जानता हैं कि चारों तरफ लुटेरों और गिद्धों का बोलबाला है। सत्ता के मद में चूर मंत्री, संत्री, कर्मचारी, अधिकारी कोई नहीं गिनता आवेदक को, सत्ता में बैठे श्वानों की फौज के लिये कानून उसकी कठपुतली है जैसा चाहे वो बलात्कार करें। जैसा चहे वो उसकी व्याख्या करें।

लोक स्वा.यांत्रिकीय मंत्री-यंत्री भ्रष्टाचार से अपना स्वास्थ्य सुधार रहें

भ्रष्ट मंत्री, प्र.स., सचिव, प्र.अ., मु.अ., का.य. सभी जुटे हैं वसूली में

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग प्रदेश की जनता के पेयजल से लेकर जल निकासी के प्रबंधन के लिये कार्य करने वाला प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग जिसमें हर कदम मंत्री गौरीशंकर बिसेन से लेकर वर्तमान में पदस्थ महाधूर्त प्रधान सचिव एस.एन. मिश्रा, जो पूर्व से ही अन्य विभागों में किये भ्रष्टाचार के लिये कुख्यात है। शायद इसलिये पदस्थ किये गये हैं, ताकि वे स्वयं भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर मंत्री की, स्वयं की और अन्य सभी के लिये वैध-अवैध धन की व्यवस्था करें, इसलिये आते ही उस हरामखोर ने सबसे पहले 5 से ज्यादा हत्याओं और सैकड़ों प्रकार की जालसाजियों के लिये कुख्यात मु. अभियंता जी.एस. डामोर को बचाके और धन कमाने के लिये उसके विभागीय लोकायुक्त के जांच अधिकारी सीबी सिंग जो एस.ई. सागर वृत्त में पदस्थ हैं, को हटाया फिर भ्रष्टाचार के लिये कुख्यात सोनगरा को मुख्य अभियंता बनाकर पदस्थ किया, जिसने सूचना के अधिकार में मांगी गई डामोर कार्यकाल की जानकारी में आग लगवाकर नष्ट कर दिया, साथ ही जो बंगला इन रेडियो कालोनी इंदौर में मिला उसमें बिना विभागीय स्वीकृति के रु. 10 लाख से ज्यादा का कार्य अवैध रूप से करवाकर, उसकी भरपाई का भुगतान अपने अधीनस्थ उज्जैन, देवास, अलीराजपुर, धार व अन्य संभागों से भ्रष्टाचार और जालसाजियों के धन से करवा दिया, इस हरामखोर का इससे भी पेट नहीं भरा, बंदे ने अपने मुख्य अभियंता होने के मद में चूर होकर तीन-तीन गाड़ियों का उपयोग कर रहा है, एक स्वयं के लिये सरकारी गाड़ी, दूसरी अपनी बेटी के लिये इनोवा जिसका भुगतान भी सरकारी मद में से अन्य संभाग कर रहे हैं। तीसरी गाड़ी अपनी पत्नी के लिये उसका भी गुगतान संभागों से हो रहा है। मुख्य अभियंता डामोर को इंदौर छोड़े हुए 5 वर्ष से ज्यादा समय गुजर गया परन्तु इंदौर के पॉश इलाके में बना सरकारी बंगला जो यशवंत क्लब के बाजु से बना है आज भी उसके कब्जे में बना है जिसका वर्तमान बाजार मूल्य किराया रु. 50-80 हजार मासिक होता है उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। जो लगभग रु. 60,000 प्रति माह के 60 महीनों के रु. 36 लाख होते हैं भी वसूला जाना चाहिये उसके वेतन से, इसी प्रकार डामोर के अंध भक्तों में एक भ्रष्ट जालसाज जो रतलाम में पदस्थ था और इंदौर से ही 8-9 वर्ष के बाद पदोन्नत होकर का.यं. के रूप में पदस्थ किया गया था इसके पास भी इंदौर की रेडियो कालोनी का इंदौर में भी बंगला था, इससे भी जन.10 से जुलाई 12 तक का रु. 15000 प्रति माह का किराया वसूला जाना चाहिए जो रु. तीन लाख से ज्यादा होता है। वसूला जाना चाहिये, इसने भी प्रोजेक्ट संभाग में रहते हुए लाखों रु. के पाइपों को टुकड़े करवा कर बिकवा दिये थे, पुनः इंदौर संभाग में पदस्थ कर दिया गया है, मात्र अपनी डामोर भक्ति के कारण, धार संभाग में करोड़ों रु. का पाईपों की खरीदी केवल मोटे कमीशन के लिये ही की गई और की जा रही है। जो पूर्व मु.अ. संकुले जो भोपाल से हर दिन अपडाउन करते थे जिसके बिलों का भुगतान भी उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, अलीराजपुर, सरदारपुर, धार के बिलों में समायोजित किया जाता था, धार में खरीदी की परंपरा व अन्य संभागों में खरीदी की परंपरा मु.अ. सक्सेना उसके बाद डामोर से लेकर अभी तक चली आ रही है। मु.अ. कार्यालय इंदौर से खरीदी के लघु उद्योग निगम को इंडेन्ट जारी होते थे, जिसमें डीआई, सीआई, जीआई पाइपों में वास्तविक खरीदी पर 10% तक झूठी खरीदी और बिल भुगतान में 25% तक का धन मिलता है, इलेक्ट्रिकल्स पंप सेट में 12% तक डकार जाता है, स्वाभाविक है आंख मींच कर खरीदी की जाती है, इसकी जानकारी पिछले वर्ष नव. 11 में मांगी गई थी। मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठा लोक सूचना अधिकारी आज-कल करते हुए 10 माह गुजार चुका है। अपील में निःशुल्क जानकारी देने का आदेश होने के बाद भी हरामखोरों की फौज अभी तक अपनी जालसाजियों के कारण जानकारी देना नहीं चाहती है।

इस विभाग के का.यं. यांत्रिकीय विभाग इंदौर संभाग से रोकड़ बही की फोटो कापी मांगी गई, इसका आकार ए-4 से दुगुना था, यहां बैठे हरामखोर जालसाज का.यं. ने व उसके सभी सहा. यंत्रियों धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा एवं सबने रु. 2/- से लेकर 4/- मांगने की अपेक्षा रु. 24/- से रु. 28/- प्रति मांग कर अपनी धूर्त मानसिकता का परिचय देते हुए शूकरों ने अपने भ्रष्टाचार और जालसाजी का भी परिचय दिया, जब इसकी अपील मुख्य अभियंता (ईएंडएम) को की गई तो उस हरामखोर ने अपनी नीच मानसिकता का परिचय देते हुए अपील खारिज करते हुए जबकि अपील की से पहले प्राकृतिक न्याय के अनुसार अनावेदक का जवाब को आवेदक को भेजना चाहिए था, बिना जवाब भेजे खारिज कर दी जबकि जिस 12/2/13 को अपील सुनवाई थी, जब जवाब के लिये लिखा गया तो तारीख बढ़ाकर 22/2/13 निर्धारित की परन्तु 16/2/13 को ही खारिज के निर्णय भेज दिया गया, यहां भी अरबों रुपए के हैंडपंपों, क्रेसिंग पाइप की खरीदी होती है। मु. अभियंता श्वास 5% अपना कमीशन आदेश पर ही नोच खाता है। जबकि कार्यपालन यंत्री लाखों रु. झूठे बिलों से डीजल, लुब्रिकेंट्स, मशीन सुधार, पाइप की खरीदी में खर्च कर रु. 3 से 4 करोड़ हजम कर लेता है। अब बेचारे का.यं. और मु. अभि. गठजोड़ के सामने आवेदक की क्या बिसात!

साप्ताहिक समय माया

शिवराज के किचन सचिवालय में महाभ्रष्टों का अड्डा

चुनावी वैतरणी व चंदे के लिये महाभ्रष्ट आई.ए.एस. खास सिपहसालार

पूरा सचिवालय डकैतों, जालसाजों से भरा पड़ा है, जो कानून को अपनी तरह से नचा कर अपनों का पोषण, निरीह जनता का शोषण करते हैं

म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के चुने हुए महाभ्रष्ट इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों को बैठा रखा है। जिसमें हाल में सेवानिवृत्ति के बाद समय विस्तार दिये गये। मुख्य सचिव आर. परशुराम हैं, जो न केवल महाभ्रष्ट वरन भारी जालसाज भी है, जिसने पूर्व में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहकर भारी भ्रष्टाचार का तांडव किया, बेशक वर्तमान में अपने समय विस्तार की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये पूरे प्रदेश के अधिकारियों, कलेक्टरों को हर वीडियो कांफ्रेंस में भारी चमकाता है, सारी कहानी के पीछे केवल दो ही तथ्य सामने आते हैं। एक तो भाजपा के मुख्यमंत्री और उसकी सरकार को जिताना और मोटे चंदे की वसूली आने वाले चुनाव के लिये, पर इस ठेके पर चलने वाले भ्रष्ट मुख्य सचिव परशुराम का पुराना इतिहास ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी इसने ही नरेगा कीराशि जो लगभग हर वर्ष रु. 5000 करोड़ से ज्यादा आती रही है, प्रति वर्ष हर जिला पंचायतों में मात्र 30 से 40% का कार्य हुआ, फिर ग्रामीण विकास में सूखा राहत, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन इंदिरा आवास योजना, मु.मं. आवास योजना, गांवों की सड़कों, बिजली, पानी आदि के नाम पर हर वर्ष मिलने वाले पूरे प्रदेश को केन्द्र और राज्य के मिलाकर रु. 1.20 लाख करोड़ रु. में न केवल इस हरामखोर ने मोटा हिस्सा हर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से डकारा वरन् उसे सूचना के अधिकार में जानकारियां न देना पड़े, इसलिये जो जिला पंचायत अधिकारी अपने विभाग का लोक सूचना अधिकारी होता था, अधिनियम के अनुसार उसमें इस जालसाज ने अपनी जालसाजी पूर्ण तरीके से उसी को अपीलेट अधिकारी बना दिया और वहां के परियोजना अधिकारी को लोक सूचना और बड़े बाबु को सहा. लोक सूचना अधिकारी बना दिया, ताकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरामखोर खुलकर हर योजना में लूटपाट करे, फिर भी पकड़ा न जाये। म.प्र. में अकेले नरेगा में ही इस धूर्त के प्रधान सचिव रहते हुए कम से कम रु. 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हर वर्ष हुआ। जिस नरेगा में 60% पैसा ग्रामीण मजदूरों को मिलना और 40% सामग्री पर खर्च होना था उसमें मजदूरी पर मात्र 20% पैसा व सामग्री पर भी 10 से 20% पैसा खर्च किया गया। जहां सड़कें नहीं बनाई थीं योजना का 70% पैसा अकेले इंदौर में मु.का.अ. गोपाल डांड ने सड़कों पर फर्जी तरीके से हजम किया। यही हाल देवास, धार, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन के साथ म.प्र. के हर जिले में किया गया। इसलिये हर जिला पंचायत में चुने हुए भ्रष्ट, निहायत मक्कारों, जालसाज धूर्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रूप में बैठाया गया, जो खुलकर संविदा नियुक्तियों जिनमें जिला पंचायतों के स्टॉफ से लेकर शिक्षकों आदि की भर्ती में वसूली कर सकें, हर मु.का.अ. से करोड़ों रु. हर माह वसूलें।

वही हाल इस धूर्त मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में भी किया, जिसमें खेत-तालाब, बलराम तालाब, राष्ट्रीय कृषि मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रति क्वि. का अनुदान, सिंचाई साधनों के लिये अनुदान, अनाज, दलहन, तिलहन के बीजों की खरीदी में अनुदान आदि के लिये राज्य और केन्द्र का मिलाकर लगभग रु. 30,000 करोड़ से रु. 50,000 करोड़ में भी इस हरामखोर गिद्ध ने खूब नौंचा खसोटी और करवाई, वहां पर इसने सूचना के अधिकार कानून में ऐसे ही जालसाजी पूर्ण आदेश जारी करके संयुक्त संचालक कृषि जिसका पूर्व में संचालक कृषि अपीलीय अधिकारी हुआ करता था, अब संयुक्त संचालक अपनो कार्यालय के आवेदन के विरुद्ध स्वयं को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया।

मुख्यमंत्री के दूसरे इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के पद से नवाजकर अपने किचन कैबिनेट में बैठाया गया है, जिनकी अय्याशी, हरामखोरी, भ्रष्टाचार आदि इंदौर की जनता ने जब वे इंदौर जिलाधीश थे खूब देखे हैं। अवैध कालोनाइजरों को इन्होंने खूब संरक्षण देकर पाला पोसा, अरबों रु. का स्टांप घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यहां से जनसंपर्क में पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी बड़े अखबारों यथा भास्कर, नईदुनिया जैसे प्रदेश के अखबारों को अनाप-शनाप विज्ञापन बांटकर अपने सभी आकाओं के विरुद्ध यथार्थ प्रगट करने में न केवल प्रदेश में वरन् राष्ट्र के सभी बड़े अखबारों यथा हिन्दुस्तान टाइम्स जिसने 5/2/13 को अपने दूसरे पन्ने पर इनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सभी समाचार चैनलों पर भी इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये अनाप-शनाप धन अपनी मर्जी से खुलकर बांटते रहे, बदले में अपने आकाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिलवाते रहे। इनकी अय्याशियों के चलती ट्रेन में किसी पत्रकार की बीबी वाले किस्से जन.10 के काफी मशहूर हुये जिसके चलते वहां से हटा दिया गया और भोपाल संभागायुक्त बना दिया गया, वहां पर भी अवैध कालोनाइजरों, भूमाफियाओं के चहेते बने रहने के साथ ही सभी इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को जो महाभ्रष्ट थे और सभी मंत्रियों के लिये मनोज श्रीवास्तव ने जमीनों, भवनों के लिये आंख मींचकर मन पसंद भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया। चुनावी तैयारी पार करने के लिये धन इकट्ठा करने, मीडिया को साधने के गुणों में माहिर मनोज श्रीवास्तव अब पूंजीपतियों, उद्योगपतियों यथा टाटा, अंबानी, बिरला आदि से दोनों हाथों से वसूली कर कानून विरुद्ध सुविधायें दिलवायेंगे, अंतिम सत्र में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में दोनों हाथ वसूली करेंगे।

तीसरे सचिव के रूप में बैठाये गये एस.के. मिश्रा पूर्व में सचिव खनिज विभाग और प्रबंध संचालक म.प्र. खनिज विकास निगम रहे। ये इस भ्रष्ट मिश्रा का कार्यकाल हीथा जिसमें मुरैना के अवैध पत्थर खनन माफियाओं ने अपने धन-बल के दम पर एक आईपीएस की आसानी से हत्या कर दी, प्रदेश के अधिकांश मु. बीओटी सड़कों के निर्माण में म.प्र. सड़क विकास निगम के अधीनस्थ 50 से ज्यादा ठेकेदारों ने लाखों करोड़ की लगभग 4000 कि.मी. सकों के निर्माण में उपयोग की गई गिट्टी, पीली मिट्टी, पत्थर मुरम की रायल्टी 5% की जमा नहीं की और मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिलकर रु. 10,000 करोड़ से ज्यादा का धन कुछ चुने हुए लोगों ने हजम कर लिया जबकि प्रदेश ही हीरा-पन्ना की खदानों से लेकर माइका, कोयला, लोहा, तांबा जैसी मूल्यवान खनिजों से लेकर गिट्टी और रेती की लगभग 10,000 से ज्यादा जगह अवैध खुदाई, ढुलाई और खनन में अवैध रूप से मिश्राजी हमारों करोड़ हजम कर गये। बेशक हिस्सा मंत्री, मुख्यमंत्री को भी मिला, इसलिए सबके प्रिय रहे, इस धूर्त भ्रष्ट मक्कार अब प्रधान सचिव लोक स्वा. यांत्रिकीय का भी कार्यभार संभाल रहा है, नियुक्ति होते ही इस श्वान ने म.प्र.लो.स्वा.यां. विभाग में बैठी डी कं. अर्थात डामोर एंड कं. के इशारों पर करोड़ों रु. का धन डकार कर नाचना शुरू कर दिया। पद संभालते ही उस जालसाज की जालसाजियों पर बैठे सभी ईमानदार जांचकर्ताओं को हटा दिया, इस डी कं. के सारे भ्रष्ट धूर्त गुर्गों को उसके मनचाहे स्थान पर बैठा दिया जिसमें मु.अ. सोनगरा इंदौर, मु.अ. सोनगरा का खास गुर्गा राजेश जोशी को देवास का का.यं., एसके. श्रीवास्तव को का.यं. इंदौर बना दिया गया, देवास का का.यं. राजेश जोशी अभी भी सारे ठेकेदारों, हैंडपंप मैकेनिकों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके एसडीओ, उपयंत्रियों के माध्यम से नगद भुगतान कर रहा है जबकि पूरे प्रदेश में सबका भुगतान ई पेमेन्ट से हो रहा है, ये श्वाम नगद भुगतान में अपना 10 से 25% धन हर योजना, टंकी, निर्माण, पाइप लाइन बिछाने आदि में हजम कर अपने उज्जैन अ.यं. शर्मा, मु.अ.सोनगरा को डी. आका और प्रमुख अभियंता से प्र.सं. तक को कर रहा है। ये है इस भ्रष्ट मिश्रा की कार्यप्रणाली और लूट।

इस शूकर की बत्तमीजी और जालसाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, खनिज विभाग ने सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं दी और उन्हें सीधे जवाब दिये, म.प्र.लो.स्वा.यां. में जब इस डामोर के स.यं. से का.यं., का.यं. से अ.यं., अ.यं. से मु.अ. और मु.अ. से सलाहकार प्रमुख अभियंता बनने के दस्तावेजों के लिये आवेदन दिया गया दिनांक 5/9/12 को स्वाभाविक था, जवाब नहीं दिया जाना था अपनी करोड़ों का दूध देती गाय का अपील की गई 17/10/12 को, अक्टूबर 12 का हरामखोर, मक्कार मिश्रा ने जवाब में लिखा अपने पत्र क्र. 16-336/2012/2/34 भोपाल दि. 21/1/13 को कि आपको जानकारी 4/7/12 को ही उपलब्ध करा दी गई, जबकि आवेदन दिनांक 5/9/12 को दिया था, ऐसे शूकरों की ही सचिवालय में सख्त आवश्यकता थी जो भ्रष्टाचार की भारी गंदगी में से भी मु.मं. शिवराज को येन-केन प्रकारेण जिता देवें। अपील वापिस कर दी गईं।

चौथे क्रम के सचिव के रूप में अजात शत्रु श्रीवास्तव जो उज्जैन के पूर्व जिलाधीश का पदभार संभाल चुके है। इस बंदे ने भी उज्जैन सभी जालसाज भूमाफियाओं और कालोनाइजरों से करोड़ों डकार कर उन्हें खूब संरक्षण दिया। इसके परिणामस्वरूप उज्जैन शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर चाहे तो इंदौर मार्ग हो, देवास मार्ग हो, शाजापुर मार्ग, आगर-बड़नगर मार्गों पर क्षेत्रीय, प्रादेशिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कालोनियों का वैध-अवैध 400 से ज्यादा का अंबार लग गया, खनिज से मिश्रा को हटाकर इन्हें प्रदेश की धरती के खनन का लूटने और लुटाने के लिये इसलिए प्रभार दिया गया ताकि वो 10,000 से ज्यादा खनन माफियाओं, ठेकेदारों, मंत्रियों और नेताओं को आंख मींचकर संरक्षण देकर हजारों करोड़ की वसूली कर चुनावी नैय्या को पार करने में शिवराज की आंख मींचकर कानूनों, राजस्व जनहित को बलाये ताक रखकर प्रदेश की धरती पर्यावरण को बर्बाद करते हुए मुक्त हस्त से मदद करते रहें।

5वें क्रम में आयुक्त, जनसंपर्क राकेश श्रीवास्तव पदोन्नत राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा बनाम इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी या सभी के यशमेन ग्वालियर और इंदौर के जिलाधीश पद पर रहकर भूमाफियाओं को संरक्षण देना, नेताओं की हां में हां करना, निहायत ढीला कोई भी महत्वपूर्ण कड़वा और बोल्ड निर्णय लेना इसकी क्षमता में नहीं, सभी अखबारों, मीडियाकर्मियों के मुंह के आकार का टुकड़ा डालकर भास्कर, पत्रिका, राज एक्सप्रेस से लेकर सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय दूर-दर्शनीय शृंखलाओं के कर्मियों को साधकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के विपरीत समाचारों को रोकना और उल्टे ही प्रशंसा करवाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से मु.मंत्री को सम्मानित करवा लेना इनकी उपलब्धियां रही हैं। चारों तरफ पूरे प्रदेश में शिव उसके गण मंत्री हर क्षेत्र में तांडव कर रहे हैं। अधिकांश समाचार पत्र ऐसे तांडवी समाचारों को नहीं छाप रहे हैं।

रा.प्र.से. से भा.प्र.सेवा में जाने के लिये यशमेन होने के साथ भारी भ्रष्टाचारी होना रु. 5 करोड़ की मोटी घूस खिलाना ही अपने आप में ही उपलब्धि हैं, शिव के सचिवालय में आगामी चुनाव तक पत्रकारों को साध कर चलने वाला ही भारी भ्रष्ट चाहिए।

6वें क्रम के सचिव विवेक अग्रवाल शिवगणों में अपने होशियारीपूर्ण तरीके से न केवल भारी भ्रष्टाचार कर अरबों रु. हजम करने के बाद भी बदनाम न होना, उज्जैन और इंदौर के जिलाधीश रहते हुये इस धूर्त ने सभी भूमाफियाओं, कालोनाइजरों को भारी संरक्षण देकर धन कमाया। अपने रिश्तेदारों को इंदौर की होटल सायाजी में ठहराने अपना रुतबा सिद्ध करने के स्वार्थ में हिन्दू कार्यकर्ताओं द्वारा 31 दिस. को इस होटल द्वारा फैलाई जाने वाली अश्लीलता के विरोध करने पर इस धूर्त ने उनके सिर फोड़ दिये थे, इसके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का पैसा उज्जैन-इंदौर से हरियाणा और पंजाब तक में निवेशित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का सचिव और म.प्र. सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक हैं ये और प्रमुख अभियंता अग्रवाल दोनों मिलकर सारे भ्रष्टों को संरक्षण देकर दोनों हाथों से बटोरने में लगे हैं। चारों तरफ इन दोनों हरामखोरों ने चुन-चुन कर महत्वपूर्ण पदों पर भ्रष्ट कार्यपालन यंत्री बैठा रखे हैं। जो 40 से 50% काम केवल कागजों पर ही निपटा देते हैं। जैसे इंदौर संभाग 1 का कार्यपालन यंत्री एस.पी. राणे, धार में रावत, इंदौर प.का.ई. में बैठा बागोले, उज्जैन में पटेल, देवास का मंडलोई आदि अधिकांश प्रदेश के अधिकांश कार्यपालन यंत्री भ्रष्ट हैं। जो 30 से 40% सड़कों को पैसा डकार कर इन तक पहुंचा रहे हैं। इस चक्कर में अच्छे कार्यपालन यंत्री जैसे सलूजा नौकरी छोड़ कर चला गया, का. यं. एपी राणे और प.कि.ई. इंदौर संभाग दोनों पदोन्नत होकर अधीक्षण यंत्री बनने की पदोन्नति धन बांटकर ही रुकवा रहे हैं। ताकि दोनों हाथों से रु. 100 करोड़ से ज्यादा के बजट में बंदरबांट करते रह सकें, दूसरी ओर जैसा कि समय माया ने प्रकाशित किया था मार्च 09 में कि केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों का न तो ढंग से विकास कर पायेगा न रख-रखाव वह सत्य सिद्ध हुआ और केन्द्र सरकार ने अनेकों राजमार्ग, रा.रा.प्रा. से लेकर लौटा दिये, उसका भी का.यं. का भार प.कि.ई. को ही सौंप दिया गया हैं, जिसमें भी खुलकर पुनः बंदरगांट शुरु हो चुकी है।

प्र.सं. विवेक अग्रवाल के बैठने के बाद म.प्र.स.वि.प्रा. अब पूर्णतः एमपी रोड डकैत कार्य में बदल चुका है। अधिकांश बीओटी ठेकेदारों ने सड़कों के विकास और इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों के अनुसार रखरखाव से ध्यान हटाकर मात्र धन खिलाकर कीमतें और टोलटैक्स की दरें बढ़वाने पर केंद्रित कर दिया है। इसे भी चारों तरफ भ्रष्टों का जमावड़ा पसंद है इसने भी लो.नि.वि. के अधिकांश भ्रष्टों को चारों तरफ भ्रष्टों और जालसाजों को ही महाप्रबंधक के पदों पर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद आदि संभागों में पदस्थ कर रखा है। यहां पर मु.अ. के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आये श्री आर.के. सावला को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, वे भी व्हीआरएस लेने का मन बना चुके हैं। पूंजीपतियों से मोटा कमीशन डकार कर उनके पक्ष में सबकुछ करते हैं। ये भी चुनावी नैय्या पार करवाने में शिव

के लिये मोटी पूंजी इकट्ठी करने में सड़क ठेकेदारों, बीओटी ठेकेदारों से वसूली में जुटे हैं। इस शूकर से सूचना अधिकार में जानकारी मांगी गई तो हरामखोर पैसे भी जमा करवा लेते हैं और कभी भी पूरी जानकारी नहीं देते, इनके खास सिपहसालारों में नरेन्द्र कुमार मु.अ., मेहरा अ.यं. का.यं. बोरासी जैसे भ्रष्टों का गिरोह कार्यरत है जिसे केवल जालसाजियां और वसूली आती है।

शिव के मुख्यमंत्री सचिवालय में 7वें क्रम में बैठाये गये मो. सुलेमान आजमगढ़िया डकैत, जहां-जहां कदम पड़े लूट और डकैती की दास्तां लिख डाली। भूतपूर्व इंदौर जिलाधीश रहते हुए प्रदेश और देश के भूमाफियाओं और कालोनाइजर्स को संरक्षण देकर पालने-पोसने और सैकड़ों करोड़ हजमकर उन्हें बिजली, पानी, सड़कों की सुविधायें भी उपलब्ध करवा दी गई। म.प्र. रोड डकैत कार्य का नाम समय माया ने इन्हीं के काल में दिया था, जहां हर सड़क ठेकेदार प्रति कि. रु. 50 लाख से रु. 2 किमी तक वसूलकर सड़कों के ठेकेदारों की लागत को इस हरामखोर ने दोगुना से लेकर छह गुना तक कर किया, पुराने ठेकेदारों ने बीओटी की सड़कों पर जहां तीन वर्ष में एक बार 7% की बढ़ोतरी होनी थी हर वर्ष में बदल दी और वाहन चालकों को लुटवाने की डकैती डालने की खुली छूट दे दी, दोगुने-चौगुने बजट बनाने में रायल्टी भी आंकी गई थी पर बंदे ने न केवल रायल्टी जमा करने का दबाव नहीं वरन् उनके सैकड़ों से हजारों करोड़ की रायल्टी में भी बंदरबांट कर छूट दे दी, इसके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा बीओटी सड़कों के निर्माण के समझौते हुए। वहां से समय माया के लगातार प्रहार के बाद हटाया भी गया तो ऊर्जा विभाग सौंप दिया, यहां पर भी इस आजमगढ़िया डकैत ने सारे थर्मल पावर प्लांटों के रखरखाव का सैकड़ों करोड़ हजम किये, कभी इस शूकर ने कोयले का बहाना बनाया तो कभी प्लांटों के बूढ़े होने और पुराने होने का बहाना बनाकर सारणी वीरसिंगपुर पाली के प्लांटों में तालाबंदी करवा दी, दूसरी तरफ इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर की ए. जल विद्युत निगम से 51% और सरदार सरोवर की 25% सस्ती बिजली न खरीदते हुए टाटा, अंबानी व अन्य से 6 से 10 गुना महंगी बिजली खरीद कर हजारों करोड़ रु. प्रतिदिन की अपनी ओर अपने आका मु.मं. की कमाई व्यवस्था की, साथ विद्युत नियामक आयोग को भी खरीदकर साल में दो से तीन बार बिजली की कीमतें इस घाटे को कम करने के लिये बढ़ाते रहे, एक तरफ जनता से कीमतें बढ़ाकर तेज गति के मीटर लगाकर वसूलते रहे तो दूसरी तरफ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से विभिन्न मदों में धन वसूल कर हजम करते रहे, अपनी वसूली के लिये और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये इस धूर्त शूकर ने सभी कंपनियों में हजारों करोड़ के घाटे दिखाकर उज्जैन जैसे अनेक शहरों में विद्युत वितरण की फ्रेंचाइजी बांटकर मंडल के हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार बनाने का रास्ता साफ कर दिया, स्वाभाविक था आजमगढ़िया की डकैती में मुख्यमंत्री भी बराबरी का हिस्सेदार है, यही हिस्सेदारी चुनाव में धन की आवश्यकता को पूरा करेंगी, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हर कंपनी अपने पैंतरे चलकर जानकारी नहीं देना चाहती।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एंथनी जेसीडी सा. शिवराज के सचिवालय के आठवें रत्न हैं। 80 के बेंच के इंडियन एब्युसिंग सर्विसेज के अधिकारी खेती को लाभ का धंधा बनाने का शिगूफा छोड़ा और कृषकों की जमीनों को कभी बांधों के लिये, कभी उद्योगों के लिये, कभी वैध-अवैध कालोनाइजरों के पक्ष में जमीनों के लिए कानून बनवायें, किसानों से गेहूं खरीदी के लिये कंम्प्यूराइज प्रणाली से पंजीयन अनिवार्य करवाकर पूरे प्रदेश के गेहूं उत्पादकों, उनकी जमीनों को डाटा इकट्ठा करवाकर पूरा डाटा बहुराष्ट्रीय कं. यथा हिन्दूस्तान लीवर, जो इंग्लैंड की युनिलीवर की भारत में सहायक कं. है, को इंडियन टोबेको कं. (जो ब्रिटिश टोबेको की भारत में सहा. कं. है। रिलायंस, सहारा व अन्य कं. को अरबों रु. लेकर बेच दिया गया, साथ ही इनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के भी ये अति. मुख्य सचिव हैं। जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश की 25000 से ज्यादा सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबों, अति गरीबों, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को लाखों टन गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल बांटने के नाम पर 25 से 50% गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल आदि खुले बाजार में बेंच दिया जाता हैं, इन 25000 से ज्यादा सह. समितियों में अधिकांश में 15 से 20 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं और सारी समितियां एकल व्यवसायी की दुकानें बन चुकी हैं। जहां खुली लूट होती है, गरीबी रेखा के नीचे का रु. 3 प्र.कि. का गेहूं रु. 3.50 से रु. 5 तक में, चावल रु. 4 का 5 से 6 प्र.कि. में खुले बाजार में रु. 20 प्रति किलो में, रु. 10 प्र.लि. का तेल रु. 25 से 40/- प्रति लीटर में बेचा जाता है। प्रदेश के 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में 95% पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेचा जाता हैं, जिसका करोड़ों रु. का हिस्सा इनके खाते में भी पहुंचता है। मु.मं. शिव को चुनावी वैतरणी पार करवाने में ये अहम भूमिका निभायेंगे जबकि पूरे प्रदेश का किसान बिफरा हुआ है। ये भले ही कृषि के राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति से ले आये हों, पर कृषकों के लगातार हो रहे हर कदम शोषण सवे जिसमें बिजली, डीज, की बढ़ती कीमतें, बिना बिजली के बिल थोपना, फिर जेलों में डालकर प्रताड़ित करना, नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों द्वारा अपनी मोटी स्वार्थ सिद्धि के लिये भूमि अधिग्रहण करना, वर्षों तक पर्याप्त और न्यायोचित मुआवजा न देना आदि शामिल हैं से पूरा प्रदेश का कृषक आक्रोशित हैं, कैसे गांवों में भाजपा को जिता पायेंगे, एंथनी यह समय परिभाषित करेगा।

म.प्र. की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के सचिवालय के नवें रत्न हैं। 1980 बैंच के अति. मुख्य सचिव आई.एस. दानी जो काफी लंबे समय से कुंडली मारे गृह मंत्रालय में बैठाकर रखे गये हैं। भाजपा अर्थात मुखेरे जानवरों की पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के शासन काल में हर किसी को नोंचने, पैसा इकट्ठा करने, जमीनों, उद्योगों में निवेश करने के लिये सबको जैसा मिले जहां से मिले पैसा आना चाहिये। इसके भाजपा को सत्ता में आने के बाद राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद इन मुखेरों से करना तो बेकार ही थी, सत्ता संभालते ही सबका ध्यान धन बटोरने में लगा था कि किसी भी प्रकार 5 वर्ष में अपना और खानदान का आने वाली 10 पीढ़ियों के लिये इकट्ठा करें। इसलिए प्रदेश में फलफूल रहे जुएं, सट्टे, वेश्यावृत्ति, नशे के कारोबार जिससे अरबों रु. हर शहर में इकट्ठा होते हैं पर नियंत्रण की तो दूर दिन-दूना रात चौगुना बढ़ा, अवैध वसूली का स्तर जो औसतन प्रदेश स्तर पर रु. 5000 करोड़ का था रु. 10,000 करोड़ हो गया। हालात ये हैं कि न केवल अवैध शराब वरन् चरस, हशीश, कोकीन से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज नशे का कारोबार पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चलकर थानों पर महीना पहुंचाया जा रहा है, वहीं हाल सट्टे का भी हैं, कितने सटोरिये प्रदेश स्तर पर पकड़े गये, नक्सलियों की तरफ देखें, तो बालाघाट से लेकर मंडला, डिंडोरी से चलकर झाबुआ के जंगलों तक फैल गया, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा के साथ ही पूरे प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। पर भाजपा के मुखेरे मुस्लिम वोटों की चाह में चुप बैठे हैं। थाने, शहर बिकने का सिलसिला थमा नहीं, बढ़ा है। उन्हें ही अधिकांश आतंकवादियों जिसमें समझौता एक्सप्रेस कांड, बंबई ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट आदि में जिन हिन्दुओं को इस आतंकवादी गतिविधियों की अ,ब,स,द भी नहीं आता, खेती किसानी से ही फुर्सत नहीं मिलती बेचारों को जिन समयों में ये कांड हुये अधिकांश लोग गांवों और घरों में होने के बाद भी उन निर्दोष हिन्दुओं का फंसाकर, इस भाजपा के हिन्दुओं के हितों को साधने के नाम से वोट झटकने वाली, स्वयं व उसका गृह मंत्रालय चुप बैठा है वरन् इस तरह से हिन्दुओं को आतंकित किया जा रहा है, इस संबंद में तथ्यों का अंबार है, जिसे जनता अच्छी तरह जानती है, हमारे गृह मंत्रालय उसके मंत्री उमाशंकर गुप्त और नव रत्नदानी जी क्या कर पा रहे, जबकि अपराधों का पंजीयन ही नहो इसलिये पुलिस का 100 नं. अधिकांश समय व्यस्त कर दिया जाता है। दावे गृहमंत्री गुप्ता, मु.मं. चौहान, पुलिस महानिर्देशक दुबे बहुत करते हैं, पर पुलिस की साइट पर कहीं भी अपराधों की जानकारी, पंजीयन तक की व्यवस्था तक हटा दी गई है। कालोनाइजर्स, भूमाफियाओं, नशा माफियाओं, जुआ-सट्टा माफियाओं, वेश्यावृत्ति करवाने वाले माफियाओं, अवैध तस्करी करने वालों, मानव तस्करी करने वालों, नक्सलियों, खनन माफियाओं द्वारा हजारों करोड़ की बंदी पूरे प्रदेश के गृह मंत्रालय तक पहुंच रही हैं, अपराधों का ग्राफ लगातार हत्याओं, डकैतियों, चोरी, लूट आदि बढ़ रही हैं। ये हैं हमारे शिव, दानी की उपलब्धियां।

लोकतंत्र में लोक द्वारा चुने गये नेताओं और राजनीतिज्ञों को सत्ता प्राप्त होते ही उनका उद्देश्य सर्वप्रथम यही होता है, कि येन-केन-प्रकरेण धन संग्रहण इसलिये आवश्यक है कि उसको सत्ता चलाने वाले वास्तविक अधिकारी घोर भ्रष्ट, जालसाज, चालबाज और उसकी मजनुसार कानून कायदों, नियमों को बलाये ताक रखकर चारों तरफ से धन की वसूली कर उसे दे रहें, प्रसार माध्यम उसकी जालसाजियां, भ्रष्टाचारों आदि को प्रकाशित न करें उसकी प्रशंसा के तिलों का ताड़ बनाकर जनता को भ्रमित करते रहे, दूसरी ओर चुनाव जीते नेताओं, राजनीतिज्ञों जो अधिकांश पढ़े लिखे भी ढंग से नहीं होते, न कोई प्रबंधन यहां तक की संविधान सभा, लोकसभा के शिष्टाचारों से वाकिफ ढंग से नहीं होते फिर वो मंत्री, मुख्यमंत्री बन जायें, तो सत्ता में बैठे घाघ इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाकर राजकाज स्वयं चलाते हुए मोटा धन डकारकर इन मुखेरे नेताओं का टुकड़े डालकर इनका मुंह बंद करके रखते हैं। ये सत्ता के वास्तविक संचालक, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव इन मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधायकों, आदि को शतरंज की बिसात पर बैठाकर मोटा माल हजम करते हुए खेलते रहते हैं। वो जानते हैं कि इन मूर्ख नेताओं को जो न तो विषय विशेषज्ञ हैं। न ज्ञानी, ध्यानी न कोई प्रबंधन का पाठ पढ़े हुए प्रबंधक, फिर इन सभी नेताओं की कमजोरियां सुरा, सुंदरी और धन है, जो इन्हें परोसते रहो इनकी औकात नहीं की ये चूंचपड़ कर लें। फिर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के पहले दो-तीन वर्ष तो समझने और सत्ता का सुख भोगने में ही गुजर जाते हैं। चौथे-पांचवें वर्ष में इन्हें फिर चुनाव और चुनाव नहीं जीत पाये तो आगे क्या होगा, इसलिये सारे श्रेष्ठ भ्रष्टों को अपने चारों तरफ बैठाकर खुली लूट-पाट की तैयारी में जुट जाते हैं। वही हाल वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने सचिवालय में किया है। जिन्होंने पिछले चार वर्षों में खूब लूटपाट की और उसके मोटे टुकड़े इनके सामने डालें। चुन-चुन इन्हें चारों तरफ मोटी जिम्मेदारियां देकर बैठा दिया ताकि अगर अगला चुनाव हार भी जायें तो इनके पास स्वयं के भविष्य के लिये लाखों करोड़ रु. की व्यवस्था हों। बैठाये गये नवरत्न इन सबमें माहिर हैं।

आयुक्त, जनसंपर्क, संचानालय जन धन बाप की जागीर नहीं

पत्रकारों का मुंह बंद करने बांटी 30 कारें और 60 एलसीडी

अपने कुकर्मों को दबाने, झूठी तारीफ छापने, भाजपाईयों को बांटे अरबों रु.

भोपाल। म.प्र. का जनसंपर्क संचानालय में बैठे आयुक्त राकेश श्रीवास्तव से लेकर उप व अति. संचालक सचिव बेलाज आहूजा मंत्री ल.ना. शर्मा, उनकी फर्जी प्रमाण-पत्रों पर नौकरी कर रही मंगला मिश्रा सं. संचालक व संयुक्त सचिव, इन्हीं मंत्री महोदय पर लटेरी थाने में 420 का मुकदमा दर्ज है, अरबों रु. के इसी जनसंपर्क संचानालय में लूटमारी से कमाये गये धन से एक विश्व विद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अपने निवास नगर में खोला है। लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण आयकर व अन्य जांच एजेंसियां इसकी जांच कर इस आय के स्त्रोत का पता लगायेंगी। वैसे तो पूरा जनसंपर्क संचानालय बाणगंगा भोपाल में बैठे सभी संयुक्त, उप, सहा. संचालकों से लेकर बाबू-चपरासी तक कमीशन खाने वाले गिद्दों का ऐसा गिरोह है, जो खुलकर कमीशन लेकर ही सारे कार्यों यथा विज्ञापन बांटना, समाचारों को देने में भी कमीशन के बिना कोई कार्य नहीं करता। जन धन की इस लूटमार में से भुखेरी जानवर पार्टी अपने प्रदेश स्थित व देश स्थित भाजपाई कार्यकर्ताओं को अरबों रु. बांट पुरुस्कृत करती रही है। गडकरी के नागपुर स्थित रेडियो स्टेशन को बंबई व महाराष्ट्र के, दिल्ली, कोलकत्ता, अहमदाबाद, बैंगलोर व अन्य सभी मेट्रो सिरीज में अपनी झूठी प्रशंसा करने अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों, आक्रोश को न छापने व प्रसारित करने के बदल करोड़ों रु. बांट रही है। हाल ही में 30 वेगन आर कारों की चाबी और 60 एलसीडी टीवी राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी न्यूज चैनल के पत्रकारों को बिन्नी नाम के बाबू के द्वारा भेजे गये, इसी विन्नी बाबु का ही रु. 2 करोड़ से ज्यादा का बंगला होशंगाबाद मार्ग के नारायण नगर में भी है। यहां कार्यरत डकैतों की फौज में आयुक्त राकेश श्रीवास्तव के बाद संयुक्त संचालक सुरेश गुप्ता, अति. संचा. आनंद गुप्ता ने हाल ही में एमपी पोस्ट डॉट कॉम के सरमनु नगेले को रु. 15 लाख के चार विज्ञापन जारी कर रु. 60 लाख का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाया गया, जिसमें सबका कमीशन था, यहां बैठे सहा. संचालक राजेश जैन जो विज्ञापन देखता है 15% से 75% कमीशन पर आंख भींचकर विज्ञापन बांटता है।

यह जनसंपर्क संचानालय वर्षभर में रु. 3000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन बांटता है, प्रदेश में, देश और विदेश में, जिसमें भास्कर जैसे पत्र समूह ही सरकार की झूठी तारीफें, उपलब्धियां छापने और इनके भ्रष्टाचार और बदनामी पूर्ण समाचारों को न छापने रोकने के बदले विज्ञापनों के बहाने रु. 200 से 300 करोड़ हजम कर जाता है, जिस महीने में चेक या भुगतान नहीं पहुंचता उसी माह से वो सरकार का यथार्थ छापकर धज्जियां बिखेरना शुरु कर देता है। अति. संचालक अनिल माथुर, बिंदु सुनील भी स. मनोज श्रीवास्तव के इशारों पर करोड़ों रु. के विज्ञापन सही खबर नाम के पांडेय द्वारा संचालित अखबार को जो कि विदिशा, भोपाल, रीवा, दिल्ली से प्रकाशन बताता है, जबकि समाचार पत्र भोपाल, रीवा, विदिशा आदि के पत्रकारों ने भी नहीं देखा है। इस डकैत गिरोह में 10 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने पुत्र-पुत्रियों, बहू, साले-सालियों के नाम से स्वयं के समाचार पत्रों के लिये वर्ष भर में रु. 100 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन जारी कर हजम कर जाते हैं। यहां पर कमीशन की दर 10% से लेकर 75% व 30% तक हैं। अब चूंकि अधिकांश बिलों का भुगतान प्रदेश और देशभर में ऑनलाइन होता है, इसलिये जनसंपर्क संचानालय के इस मुख्यालय में किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि कितने करोड़ के विज्ञापन किसको बांट दिये गये। इसलिये ये डकैतों का गिरोह किसी को भी सूचना के अधिकार में किसी को एक पेज की जानकारी देने के नाम पर सारी नौटंकी करते हैं पर जानकारी नहीं देते। जबकि मंत्री की जनसंपर्क अधिकारी मंगला मिश्रा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनकर इस कार्यालय में लगी थी, अपने तन-मन के समर्पण और सेवा के चलते सहा. संचालन जाली प्रमाण पत्रों के दम पर ही बन बैठी। एक जालसाज महिला बिंदु सुनील भी म.प्र. की मूल निवासी न होने के बाद भी सहा. संचालक बन बैठी है। इसने भी तन-मन से अधिकारियों की सेवा समर्पण से ही सब प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी न्यूज चैनल के पत्रकारों को न केवल कारें, एलसीडी और अरबों रु. के विज्ञापन बांटकर अनुग्रहित किया जाता है, जबकि प्रदेश के ही हजारों साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक के पत्रकारों से डीएवीपी, डीपीआर, फाइलें, औपचारिकतायें तो पूरी करवाता है पर विज्ञापन के नाम पर उन्हें संविधान में पत्रकारों की आजीविका हेतु वित्तीय सहयोग देने के प्रावधान के बाद भी ये शूकरों की फौज जन-धन के प्रसार-प्रचार के विज्ञापन बजट के रु. 3000 से ज्यादा करोड़ के बजट को अपने बाप की जागीर की तरह उपयोग कर अपनी झूठी प्रशंसायें छपवाकर देश-प्रदेश की जनता को भ्रमित करते रहते हैं।

साप्ताहिक समय माया

चीटांबर बजट नौटंकी 13-14 जनशोषक पूंजीपति पोषक

पेज 1 का शेष

अच्छे उद्यमी नहीं चाहिये, जो स्वयं के उद्योग धंधे लगाकर दूसरों को रोजगार दे सकें।

निर्माण फंड रु. 1000 करोड़ व विकास रु. 2000 करोड़ - इस निधि का सारा पैसा राज्य सरकारें झूठे कागजी आंकड़ों की भ्रष्टाचार की खेती में खाद, पानी देने में ही पी जायेगी जिसमें पुलिस सुरक्षा के नाम, आदिम जाति कल्याण विभाग ही पूरे देश के राज्यों के जिला सहा. आयुक्त पीते आये हैं और भविष्य में भी पी जायेंगे।

अनु. जाति उपयोजना रु. 41561 करोड़, अजजा- रु.245980 करोड़

गणतंत्र की स्थापना से 13-14 तक रु. 25 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद भी ये धूर्त सत्ता तंत्र उनकी तीसरी पीढ़ी को भी आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहता। बेशक अनु.जाति और जनजाति का 50% धन राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, दूसरी और यदि अजा, अजजा यदि आत्मनिर्भर हो गया और सरकारी दान और भीख से उनके पलने की आदत समाप्त हो गई, तो इन हरामखोर धूर्त कांग्रेस को वोट बैंक ही समाप्त हो जायेगा, फिर हिन्दुओं में झगड़ा-पिछड़ों का विवाद समाप्त हो गया तो कांग्रेस बनाम करप्शन ओरिएंटेड नोटोरियस गैंग ऑफ एक्सटार्शन एंड रिसोर्सस सर्किंग सर्विसेज का आस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

कृषि रु. 9900 करोड़ रा.कृषि विकास योजना और रु. 22500 करोड़

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए दोनों योजनाओं में रु. 32400 करोड़ से यथार्थ में कृषकों को सीधा प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले वर्षों में खर्च किया गया। सारा पैसा केवल कागजी ज़मा खर्च करके, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से लेकर राज्यों के कृषि मंत्रालयों द्वारा जिलों में कृषि उपसंचालकों, सहायक संचालकों के माध्यम से कागजी खानापूर्ति करके ही हजम कर लिया गया। इस वर्ष भी यही किया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि पूरे कृषि मंत्रालयों को इतना भ्रष्ट बना दिया जाये ताकि बहुराष्ट्रीय कं. को कृषि उत्पादों के साथ कृषि भूमि हथियाने में कोई बाधा और व्यावधान न रहे, इस तथ्य का यथार्थ इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कृषि पर इतना खर्च करने के बाद भी कृषक कर्ज के मकड़जाल में उलझकर आत्महत्या कर ही रहे हैं।

रक्षा बजट रु. 2.09 लाख करोड़ ताकि सुरक्षा के नाम जहाजों, लड़ाकू विमानों टैंकों, तोपों, मिसाइलों की खरीद आदि में 5% से 50% तक कमीशन डकारा जा सकें, भारत विश्व में पहले क्रम का हथियार खरीदार राष्ट्र है, क्योंकि खरीदी में ही मोटा कमीशन मिलता है, अनुसंधान विकास और हथियारों के उत्पादन से जो मिलेगा तो राष्ट्र को मिलेगा सत्ताधीशों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा।

महिला रु. 97134 करोड़ व बाल विकास रु. 77236 करोड़ अर्थात कुल रु. 174,170 करोड़

यथार्थ में 10% भी महिला व बाल विकास में खर्च नहीं किया। 90% पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से लेकर एकीकृत बाल विकास योजना कार्यक्रम, जिला म.बा. कार्यक्रम अधिकारी से लेकर आयुक्त और मंत्री ही डकार जाते हैं। महिला और बाल उपस्थिति पंजी में दिखाई संख्या के मात्र 2-5 से 10% बच्चे और महिलायें मुश्किल से आती है। कई आंगनवाड़ियां तो कई दिनों तक खुलती नहीं है, पर हर आंगनवाड़ी में 80% से 100% तक उपस्थिति दिखाकर पूरे देश में 60 से 95% धन हजम कर लिया जाता है। यथार्थ में 90% यह धन भी भ्रष्टाचार में डूब जाता है, दूसरी ओर सरकार इस मद में 90% यह धन हजम कर जाती है, तो 90% महिला और बाल सरकारी सहायता के मोहताज भी नहीं, अर्थात इस सरकारी भीख के आदि नहीं जो शुभ संकेत है। राष्ट्रीय विकास के लिये आत्मनिर्भर लोगों की आवश्यकता हैं, न कि दान और भीख पर पलने वालों की।

शिक्षा रु. 65867 करोड़ और सर्वशिक्षा अभियान रु. 27000 करोड़

कुल रु. 92867 करोड़- केंद्रीय विद्यालयों के वेतन व अन्य खर्चों के पूरे वर्ष के बजट में अगर शामिल हैं तो भी वास्तविकता में जब अधिकांश 80% शहरी शिक्षा और 50% ग्रामीण शिक्षा जब निजी क्षेत्रों में है पूरे भारत में आखिर ये रु. 60,000 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार में पी लिया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान का 80% पैसा सरपंचों से लेकर शहरी जिला सर्वशिक्षा अभियान अधिकारी निर्माण व अन्य सुविधाओं का हर जिले में हजम किया जा रहा है।

ये जानकारी सूचना अधिकार में इंदौर सर्वशिक्षा अभियान से निकाली गई थी। इसमें मु.का.अं. जिला पंचायत भी हिस्सेदार होता है, शीघ्र लेकर सब बंदरबांट में पिछले 10 वर्षों में हजम किया गया, अधिकांश राशि सरपंचों को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिये दी जाती हैं तो सब हजम कर जाते हैं। उनके विरुद्ध पूरे देश में इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

स्वास्थ्य रु. 37330 करोड़

इस राशि से आशा कार्यकर्ताओं से लेकर पूरे देश में राज्यों के अस्पतालों के डॉक्टरों, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संचालक, स्वास्थ्य मंत्रियों का स्वास्थ्य ही सुधार होता है। 25% से ज्यादा राशि भी वास्तविकता में जनता के स्वास्थ्य पर खर्च नहीं की जाती, 50-60% निजी नर्सिंग होम्स में ही जनता अपना स्वास्थ्य सुधार कर जीवन चला रही हैं।

मिड डे मील में रु. 13215 करोड़

इसके पैसे में भी पिछले वर्षों का इतिहास बताता है कि इस योजना का अधिकांश धन जिला पंचायत अधिकारियों से लेकर सरपंचों तक कैसे हजम किया जा रहा है। केवल 30% धन का भोजन ही खेतीहर व आम मजदूरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मिलता है। वे सड़े गेंहू, दाल चावलों का, पूरे देश के समाचार पत्र प्रकाशित करते रहते हैं। कुल मिलाकर आम जन को इस बजट से जो रु. 3 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन बाजार में आयेगा रु. की कीमत गिराकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करेगा फिर ऊपर से यह धन ज्यादा वायदा बाजार में लगाकर आम जिंसों यथा तेल, शक्कर, गेहूं, चावल, दालों की कीमतों में वास्तविक वृद्धि करेगा, दूसरी ओर आयकर की सीमा में जो वृद्धि की गई है वो आम गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार जिसका वेतन रु. 5 से 20,40 है बच्चों की बढ़ती पढ़ाई की कीमतों, पेट्रोल-बिजली में ही आधे से ज्यादा समाप्त हो जाने के कारण गरीब जनता को भूखा सोने पर मजबूर करेगा। चीटांबर वित्त मंत्री ने आंकड़ों की बाजीगरी के साथ ही केवल वोट और नोट बैंक का सीचिंत करने का ही प्रयास है।

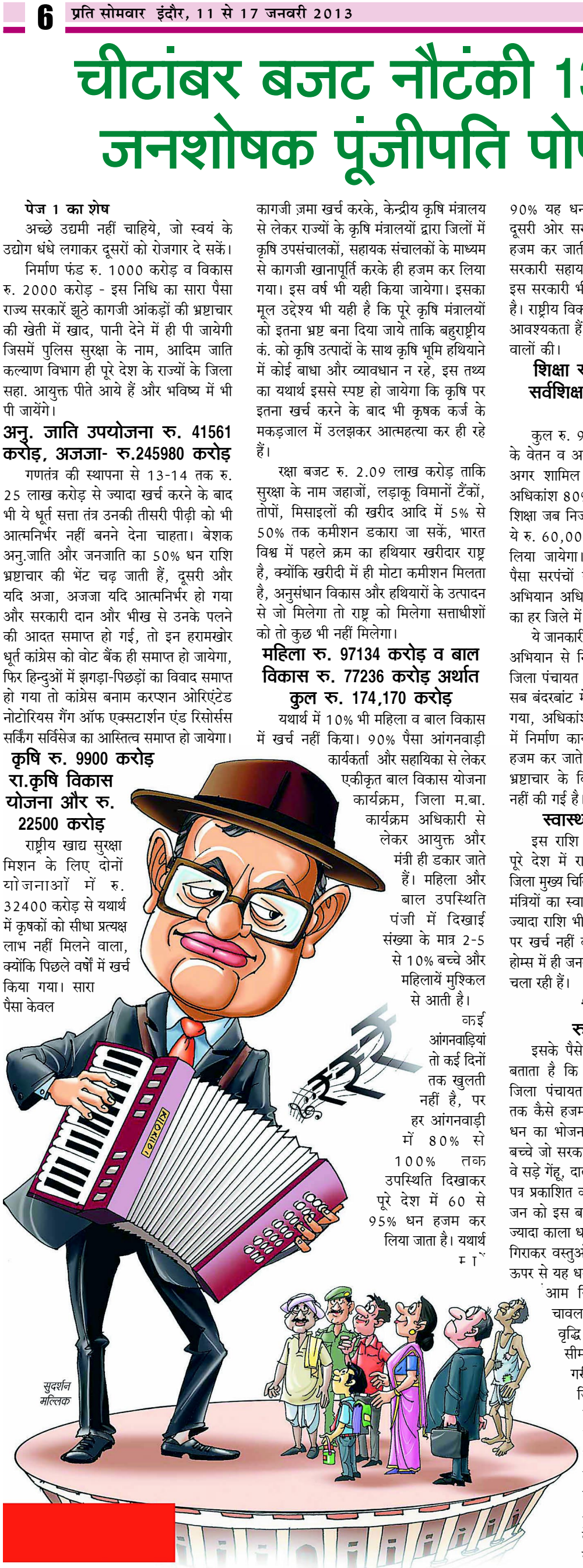

संक्षिप्त विशेष समाचार

इंदौर नगर निगम- चारों तरफ मची है लूट

पार्षदों की जालसाजियों से बच्चा-बच्चा अनभिज्ञ नहीं है, इन हरामखोरों ने अपनी कमाई के लिये अच्छे खासे लगे हुए टाइल्स को पहले थोड़ी बहुत से तुड़वा दी, बाकी बची हुई निकलवा कर पुनः लगवाकर सीमेंट कांक्रीट सड़कों पर भी पुनः 1 फुट मोटी करीब 50 कि.मी. से ज्यादा कांक्रीट की सड़कें बिछवा दी गई, अनावश्यक रूप से स्पीड ब्रेकर बनवाकर सभी 69 पार्षद लाखों के बिल हजमकर रहे हैं। वही हाल उस क्षेत्र के बगीचों में किया जा रहा है, वहां जानबूझकर सीमेंट की बेंचों को जालियों को, दीवारों को, फव्वारों को तोड़ा गया। अनेकों वृक्ष कटवा कर लकड़ियों का सदुपयोग किया जा रहा है, फिर उनके निर्माण कार्य करवाकर भी लाखों रु. के बिल, महापौर और आयुक्त के साथ कमीशनखोरी कर हजम किये जा रहे हैं।

कृषि विभाग

संदौर के उपसंचालक पद पर बैठे आलोक मीना का जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं, जिसकी सूचना के अधिकार में वर्षों से जानकारी नहीं दी जा रही है। 1970 के बाद से मीना म.प्र. में सामान्य वर्ग में घोषित किये गये हैं। वहां बैठे धूर्त संयुक्त संचालक रघुवंशी से जानकारी मांगी गई परन्तु वह महा भ्रष्ट भी जानकारी देने में नाकाम रहा, आलोक मीना उपसंचालक इंदौर में ही परन्तु विभागीय खरीदी अपने आपूर्तिकर्ता मित्रों से परस्पर लाभ के लिये शाजापुर से कर रहे हैं। इनके अधीनस्थ भूमि संरक्षण अधिकारी भी खेत का पानी खेत में बलराम तालाबों में अनुदान की बंदरबांट में जुटे हैं। खाद, बीज, कीटनाशकों संभालने वाले अधिकारी भी अपने संरक्षण में नकली, स्तरहीन गुणवत्ताहीन माल बिकवाकर गरीब किसानों की बर्बादी का कारण बने हुए हैं। बीजों की किट वितरण में भी अंधों की रेवड़ी की तरह चीन्ह-चीन्ह के बांटे जा रहे हैं और आधा माल खुले बाजार में बिकवा दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश अधिकारी यात्रा भत्तों से लाखों रुपये के झूठे बिल लगाकर हजम कर चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में जांच की जाकर लोकायुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए, यही हाल पूरे प्रदेश का है। जिसकी सत्यता सूचना के अधिकार में प्राप्त इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, शाजापुर के दस्तावेजों से होती हैं।

पंजीयन कार्यालय

यहां 70% भूमि, भवन व अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय के पंजीयन में जालसाजियां की जाती हैं। यह कार्यालय शहर में स्टांप घोटाले, आपूर्ति में वसूली और विलंब का भी जिम्मेदार हैं, 1 अप्रैल से मुद्रांक विक्रेताओं को अपनी अनुज्ञप्तियों का पुर्न नवीनीकरण कराना होगा जिसमें रु. 10,000/- प्रति अनुज्ञप्ति वसूला जायेगा, जबकि मुद्रांक विक्रेताओं को रु. 1000/- से 2000/- प्रति माह की रिश्वत, स्टांप प्राप्त करने व अन्य खानापूर्तियों के लिये दी जाती हैं। पूरे म.प्र. में और देश का यही सर्वमान्य सत्य हैं।

सहकारिता विभाग

अपने भ्रष्टाचार पूर्ण कारनामों के लिये भूमाफियाओं, साख समितियां, सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने और करवाने के लिये वर्षों से प्रसार माध्यमों की सुर्खियों में रहे हैं। इसके विपरीत प्रदेश की 20,000 से ज्यादा राशन दुकानों, ग्रामीण सहकारी समितियां जो सभी सहकारिता के अंतर्गत आती हैं। 10-20 वर्षों से न तो इनका अंकेक्षण किया जा रहा हैं, न साख, ग्रामीण और शहरीय राशन दुकानों के चुनाव आदि करवाये जा रहे हैं। वहां बैठे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष केवल कागजों पर ही हैं, जो कागजों पर सारी खानूपर्ति कर एकल स्वामित्व की दुकानों के रूप में ही 10-20 वर्षों से चलाये जाकर गरीबी रेखा का गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी के तेल आदि का मात्र 20-25% वितरण कर खुले बाजार में बाजार कीमतों से 10-20% कम कर बेंच कर हर वर्ष लाखों रु. कमा रहे हैं। यहां बैठे जिला आपूर्ति अधिकारी बनाम नियंत्रक, सहा. आपूर्ति अधिकारी, निरीक्षक इन राशन दुकानों से महीना लाखों रु. में वसूलकर इस काला बाजारी की तरफ से आंख मींचे रहते हैं। जब इसकी शिकायत मंत्री पारस जैन और प्र.स. स्वाई से की गई तो दोनों ही शूकर वाले की सहकारिता में चल रही इन दुकानों की शिकायत पंजीयक, उपपंजीयक सहकारिता को करो अर्थात हमारी वसूली में दखल मत दो।

जनता व मीडिया का ध्यान बंटाने कांग्रेस ने रचे क्रमिक षड्यंत्र

पेज 1 का शेष

जब चारों तरफ आक्रोश की आग में देश जलने लगा और 15-20 दिन गुजर गये, मोदी की जीत का प्रभाव ठंडा हो गया तो फिर मौनी बाबा ने मीडिया को छोटा सा वक्तव्य जारी कर ठीक है बोल कर सिद्ध कर दिया कि सब पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ही सारी कार्यवाही की गई अन्यथा कांग्रेसी राजकुंवर को प्र.मं. के पद के दावेदार के रूप में भूल जाते और मोदी युवाओं के सर्वमान्य महानायक मीडिया और जनता के मस्तिष्क पर हावी हो जाते।

दूसरी घटना
सर कलम सैनिक थे या गाजर मूली, दूसरे क्यों देखते रहे

कांग्रेस सत्ता सुख भोगे, कुंवर की ताजपोशी करें या युद्ध करें। सेना को वेतन तो सिर कटाने का ही देते हैं, सैयद साहब, स्व. ओसामा जी आप को जो करना है, कीजिये, हम तो इसे भी हिन्दू आतंकवाद का नाम देकर काम चला लेंगे

हम कांग्रेस हैं, हमारी मूल परिभाषा ही है, करप्शन ओरिंटेड, नोटोरियस गैंग ऑफ रिसोर्सेस एक्सटार्शन एंड सर्किंग सर्विसेज है, अर्थात हम भ्रष्टाचार मूलक शैतान गिरोह है हमारा कार्य स्त्रोतों का शोषण और चूसना सेवा है। हमारे आका अंग्रेजों ने जिन्होंने हमारी स्थापना की थी, आजादी देकर जाते समय उन्होंने जिस गुरुमंत्र से इस विशाल देश पर शासन किया था, फूट डालो और राज्य करो की नीति के अनुसरण में हम असली आतंकवादियों का सम्मान और वे सभी हिन्दु जो हमें वोट नहीं देते हैं। हमारे कुकर्मों, भ्रष्टाचारों, लूट-पाट, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध करते हैं वो सब हमारी दृष्टि में आतंकवादी ही होते हैं। फिर हमें अगड़े हिन्दू वोट भी नहीं देते हैं। हमारी वोट बैंक वैसे भी आपकी कौम के मुस्लिम और एससी, एसटी हैं।

कांग्रेस ने ही जानबूझकर सर कलम करवाये अपने सैनिकों के ताकि मीडिया और जनता का ध्यान मोदी से हटकर दो सैनिकों के सिर काटने की घटना में उलझे रहें। फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या सीमा पर दो ही सैनिक थे और सिर काटने वालों के पास 100-50 लंबी तलवारें थीं जो उन्होंने दो सैनिकों के 100 दूरी से सिर काटे और 125 करोड़ लोगों की अस्मत पर हाथ डालकर काटकर ले जाकर उससे फुटबाल खेली और दूसरे सारे सैनिक ताकते रहे, क्या वो अपनी एके-47 और मशीनगनों की गिटार बजा रहे थे और मौज मस्ती में डूबे थे। क्या इस देश की जनता के खून-पसीने से वसूली गई राशि से जो वेतन मिलता है, कि अपने साथियों की गर्दन कटते देखते रहें, यदि वो 100-200 गोलियां बरसा कर उन्हें ढेर कर देते तो क्या बिगड़ जाता, पर इन शूकर कांग्रेसियों के मस्तिष्क में राष्ट्र की मान-शान नहीं देश को लूटना-खाना, धन बटोर कर विदेशों में जमा करवाना बसा है। दो गर्दन ही क्यों उड़ाई, 100 ले जाओ सैय्यद साहब, हमें तो हिन्दुओं का आतंकी बताकर डराने-धमकाने, बेइज्जती करने का सुअवसर उपलब्ध करवाया है आपने।

तीसरी घटना
अफजल गुरु की फांसी की नौटंकी

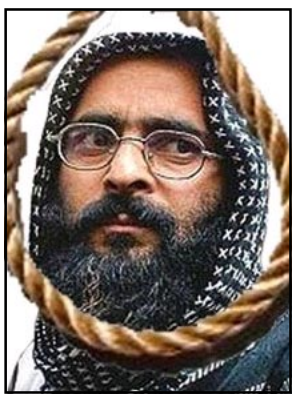

अंग्रेजों की अवैध औलाद कांग्रेसियों की औकात है, कि वो किसी भी मुस्लिम को फांसी पर चढ़ा दें, यह नौटंकी मोदी की लोकप्रियता से ध्यान हटाने के लिये 2003-04 में ही फांसी की सजा देने के बाद अचानक 2013 में क्रमिक नाटक खेलने का ही हिस्सा थी, उसे भी दाड़ी काटकर जिंदा भगा-या गया, यदि राष्ट्रद्रोही आतंकी था, तो क्यों नहीं ईरान, ईराक व अन्य मुस्लिम राष्ट्रों की तरह सार्वजनिक फांसी दी गई, सुरक्षा कारणों का मान भी लिया जो विडियो से ही अपनी राष्ट्र भक्ति का सबूत दे देते, फांसी पर लटकाने, लाश को दफनाने का पर कैसे?

चौथी घटना
कुंभ में भगदड़ में 80 मरे, 600 घायल

इलाहाबाद कुंभ में पूरा कुंभ शांति से सारे स्नान पूरे हो रहे थे, लाखों श्रद्धालु हर स्नान पर आ जा रहे थे, पर हर स्नान पर मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा साधु-संतों और नेताओं के बीच बढ़ती जा रही थी, जो डकैत कांग्रेसी धूर्तों को हजम नहीं हो रही थी, तो केन्द्र शासित यह कांड रेलवे स्टेशन पर किया गया, जब लाखों यात्री प्लेटफार्म पर हो, तो स्वाभाविक 4 नं. प्लेटफार्म की घोषणा को रेल आने के बाद बदला जायेगा, तो यात्री भटकेंगे और भागदौड़ मचायेंगे, ऐसी भीड़ में छोटी सी घटना भी सैकड़ों की मौतें और हजारों के घायल होने का कारण बनेगी ही, शासकीय स्तर पर हर जगह मरने और घायल होने वालों का एक शून्य घटाकर बताने का कांग्रेसी चलन तो अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है, बेचारी कांग्रेस तो उस परंपरा का निर्वहन कर रही है।

फिर कांग्रेस की इस भगदड़ की मौतों और घायल की सोची-समझी और पूर्व नियोजित साजिश से एक पत्थर से कई निशाने साधे गये, जिसमें मीडिया और जनता का ध्यान मोदी से हटाने के साथ ही सपा की उ.प्र. सरकार से, सरकार का साथ छोड़ने का बदला लेना भी था, ताकि सपा को नीचा दिखाया जा सके और अगले लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम सांसद चुने जा सके, इसका असर भी दिन से ज्यादा रहा, मोदी जो गांधी कुंवर का प्रतिद्वंद्वी है, ध्यान तो हटाया ही।

पांचवी घटना
हैदराबाद में आतंकी विस्फोट

कांग्रेस का आतंकवाद, सत्ता चलाने, अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने का 300 वर्ष पुराना हथियार है, आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही रहे, उन्हें बचाकर मुसलमान वोट बैंक को हथियाना, दूसरा घटना के ठंडे होने के बाद सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एसटीएफ, एटीएस जैसी सारी एजेंसियों का उपयोग हिन्दुओं को पकड़कर बलि का बकरा बनाना, आतंकित करना, खौफ पैदा करना हिन्दुओं में उन्हें बदनाम करना, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दु महासभा आदि के नेताओं के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, गिरफ्तारी कर भयानक प्रताड़ना देकर अपराध स्वीकार करवाकर अन्य कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना, कांग्रेसी षड्यंत्रों के विरुद्ध बोलने से रोकना आदि का पुराना इतिहास रहा है। इसके विपरीत आतंकवादियों का सैय्यद साहेब, ओसामा जी बोलकर मनोबल बढ़ाना, ताकि वो आतंकी भविष्य में भी तांडव कर सकें। घटते क्रम में पेट्रोल की सप्ताह भर में दो बार कीमतें बढ़ाकर जनता और राजनैतिक पार्टियों को आंदोलन करने, दंगा भड़काने के लिये विवश करना, ताकि लोकसभा सत्र में संसद कुकर्मों पर बोलने की अपेक्षा बहस करवाने की अपेक्षा, जैसा कि हेलिकाप्टर कांड में सरकार की धज्जियां बिखरने वाली हैं से बचने, मोदी की छवि को दबाने, पेट्रोल की कीमतों के बम की पिन खोलकर मीडिया जनता और राजनीतिज्ञों के सामने उछाल दिया गया है, कांग्रेस को जनता से धन लूटने, कीमतों को बढ़ाकर आतंक फैलाती है।

सुंदरियों और भ्रष्टों का बोलबाला, मेहनतकशों का मुंह काला

पेज 8 का शेष

पर इन धूर्तों आयुक्त प्र.सं. और मंत्री जैसे धूर्तों को शासकीय राजस्व से नहीं अपनी इच्छापूर्ति और कमाई से मतलब हैं, दिस-जन. वसूली के महीनों में एक मेहनतकश अधिकारी का मनोबल तोड़ते हुए धकिया कर खंडवा स्थानांतरित कर सोनी को बैठा दिया गया, जब तक सब कुछ समझ आयेगा तब तक वित्त वर्ष 2013 समाप्त हो चुका होगा। अरबों रु. का घाटा होगा या वसूली नहीं आयेगी तो शासन की नहीं आयेगी, वही हाल श्रीमती सोनाली जैन के मामले में किया गया। पहले उसे इंदौर बुलवाया गया। 6-8 महीने भी नहीं हुये थे कि उसे खुश करने के लिये उसे भरी जन.फर. के मध्य में उज्जैन स्थानंतरित कर जहां वृत्त 2 में सहा. आयुक्त का पद नहीं भी था, उसके लिये पद निर्मित कर दिया गया। जैसे इन शूकरों के बाप की जागीर हो। मंत्री, संत्री, पीएस और आयुक्त की अपनी और अपनी चहेती के लिये पद निर्मित कर उसे उपकृत किया जाये।

वही हाल वा.क्र. आ. प्रीति जौहरी को भी सेंधवा बेरियर पर भारी कमाई के लिये पहुंचाया गया। जबकि अधिकांश उच्च पदों पर बैठी महिलायें न केवल भ्रष्ट, चालाक और कामचोर हैं। वरन अपनी कमाई के लिये सब कुछ कर पहले कमाई वाले पद हथियाना और पिर जिम्मेदारियों में जिनमें कमाई हो उसके लिये सबसे आगे वरना अपना काम भी अपने मातहतों के जिम्मे कर बहानेबाजी कर अपनी सीट से गायब रहना, ये हाल वृत्त इंदौर वृत्त 11 श्रीमती रानी सोनी का भी है, यही हाल उज्जैन में बैठायी गई श्रीमती सोनाली जैन का है, वे भी ता. 28/2/13 को लंच से 4 बजे लौटी, 1 घंटे में अपने रुतबे का प्रदर्शन कर 5 बजे फिर गायब, सरकारी कार्य है, मंत्री, पीएस, आयुक्त से सेटिंग हैं, 4 बजे आई, ये गाड़ी हटाओ वो गाड़ीहटाओ, जैसा कि पुलिसिये अधिकारी अपना रुतबा झाड़ने के लिये करते हैं। उनके नगर सेना के ड्राइवर ने भी किये, ऐसे पुलिस अधिकारी पति की पोस्टिंग शासन को बालाघाट, मंडला, मुरैना में करें और पत्नी को भी जिसमें अधिकारी होने का घमंड है, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि जन-धन से प्राप्त वेतन और सुख-सुविधाओं की कीमत भी चुकानी पड़ती है।

अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या शासन में बैठा मंत्री राघवजी, पीएस, आयुक्त को शासन ने शासकीय कार्य करने और राजस्व वसूलने के लिये बैठाया है या अपनी इच्छापूर्ति और कमाई के लिये बैठाया है, क्या कानून अपने बाप की जागीर है, जिसे जब चाहे जैसा तोड़ा मरोड़ा जाये, जब चुनाव अप्रैल, मई, जून में करने का प्रावधान हैं, तो इन हरामखोरों, जालसाजों ने कैसे और क्यों स्थानांतरण कर शासन को अरबों रु. की राजस्व हानि पहुंचायी गई, जिन तीनों के स्थानांतरण किये क्या वो खुश हैं अंतरयामी हैं जो पद पर बैठते ही सारी कहानी समझ कर तत्काल राजस्व वसूलने की कार्यवाही कर सकेंगे। दूसरी ओर इंटी इवेजन ब्यूरो अ और ब इंदौर में बैठे सारी निरीक्षकों से लेकर सहा. वा.क.अ., 2-2 वाणिज्य कर अधिकारी, 1 सहा. आयुक्त और उपायुक्त सब कमाई में जुटे रहकर शासन को केवल औपचारिकतापूर्ण आय उपलब्ध करवा रहे हैं। अधिकांश समाचार पत्र इनकी जालसाजी पूर्ण महीना वसूली के बाद बसों पर समान लादने के फोटो छाप चुके हैं। ट्रांसपोर्टरों से दोनों ही संभाग रु. 5 से 10 करोड़ तक वसूली आंख मींच कर करने के कारण अवैध गुटखा पाऊच, सिगरेट से लेकर अरबों रु. का माल बिना बिल्टी के बेच रहे हैं। यहां बैठा हर निरीक्षक और सहा. वा.कर. अधिकारी प्रतिदिन औसतन रु. 50 हजार से लेकर 80 लाख रु. तक की कमाई करता है, विंग अ में बैठी महाभ्रष्ट, चालाक और शीर्ष सहा. वा.क. अधिकारी प्रतिमा करारा जिसके देवास में भ्रष्टाचार वसूली के लिये सब कुछ करने को तैयार, जिसने विभाग की छवि को काफी उज्जवल किया था, इंदौर के एंटी इवेजन में बैठकर ट्रकों, ट्रालों, ठेलों को पकड़ने के बाद उनसे 2 गुना पेनाल्टी बनाने के बदले 5 गुना पेनाल्टी के बीच 10 से 25% वसूल कर जिसका सौदा चेतक चेंबर और छावनी की चाय-पान दुकानों पर वसूली कर छोड़ देने का कार्य कर रही हैं, बेशक मंत्री, प्र.स., आयुक्त लाखों रु. लेकर ही यहां नियुक्ति देते हैं, तो क्यों? जब ये निरीक्षक अधिकारी पैसा देते हैं, तो कमाई के लिये ही, इसमें सबसे बड़ी जालसाजी निजी ठेके पर सुरक्षा गार्डों, टैक्सियों का उपयोग कर दलाली खाने का हैं, ये निजी गार्ड, टैक्सी वाले जिस दिशा में जाते हैं, इन अधिकारियों-कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही सूचित कर देते हैं। ताकि इन अधिकारियों को कुछ हाथ न लगे।

वैसे तो पूरे देश के राज्यों के सभी शासकीय विभागों में दलालों का साम्राज्य है, पर अधिकांश विभागों में दलालों की वैधानिकता नहीं हैं, परन्तु यहां दलालों को वैधानिकता प्राप्त है, इसलिये ये दलाल एक तरफ तो कर्मचारियों अधिकारियों को चमकाते-चमकाते हैं। स्थानांतरण करवाते हैं, भ्रष्ट को ईमानदार और मेहनतकश और मेहनतकशों को निकम्मा ठहराते हैं। वहीं व्यापारियों को कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम से और कानून के नाम से डरा धमकाकर दोनों तरफ से धन डकार जाते हैं। सबसे ज्यादा क्रीम अभी ये ही चाट रहे हैं। जिससे अरबों करोड़ की शासन के राजस्व की हानि हो रही है, वैसे व्यापारी फर्में भी भारी मूर्ख हैं जब अधिकांश वाणिज्य कर का कार्य आनलाइन होता है और व्यापारियों को स्वयं ही करना होता है, तो इन बिचोलियों और सलाहकारों को बीच में से स्वयं ही हटा देना चाहिये, व्यापारियों को प्रोत्साहित कर शासन को स्वयं विभागीय जनसंपर्क अधिकारी बैठाकर उन्हें कर निर्धारण और समय पर कर जमा करवाना चाहिये।

बेशक मंत्रीजी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिये जब तक पद पर हैं, अधिकांश सुविधाओं को भरपूर मांगना उनकी नियति है, कल टिकट मिले न मिले चुनाव जीते न जीते इसलिये आवश्यक है नियम कानून को बलाये ताक रखकर एकमात्र मूल मंत्र बनिये का वसूली और वसूली ही होना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

बजट सत्र समय पूर्व समापन की तैयारी

अपने ही कुकर्मों से भयभीत भाजपा

मार्च में ही सत्र समाप्ति के लिये षडयंत्रपूर्वक विवाद खड़ेकर भागेंगे

भोपाल। वर्तमान में म.प्र. की सत्ता संभाल रही भाजपा के शासन और कार्यकाल की यह विशेषता रही है कि उसने अपने सभी विधानसभा सत्रों को समय पूर्व समाप्त कर दिया ताकि उसके भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विपक्ष सत्ताधीश मंत्री और मुख्यमंत्री को न घेर सके, ताकि कम से कम बदनामी सत्ताधीशों की और जबरदस्ती में विपक्ष को मौका न मिल सके, यदि विधानसभा के सत्रों को पूरा चलाया गया तो विपक्ष सरकार की हर नाकामी, भ्रष्टाचार, लूट-पाट पर सरकार में बैठी भाजपा के मंत्रियों, मुख्यमंत्री से पूछताछ कर हर सवाल का जवाब मांगेगा, ये सत्ता में आ जरूर गये, परन्तु न तो इन्हें ढंग से सत्ता चलाना आता है, न ही अपने मातहतों पर नियंत्रण करना, इसलिये ये हर विधानसभा के हर सत्र को समय से पूर्व ही भाजपाई रणछोड़दास सत्र के समापन के लिये षड्यंत्रों की रचना करते हैं कि कैसे विवाद पैदा किये जायें। विपक्ष को उकसाया जाये, विवाद पैदा कर उसको बढ़ाया जाये और फिर आसानी से समापन करने की घोषणा कर दी जाये। इसलिए विपक्ष के नेता को पहले से ही शाम, दाम, दंड, भेद की नीति पर चलकर धन बांटकर भी येन-केन प्रकरेण सत्र समाप्त करवा दिया जाता है। पूर्व में विपक्ष की नेता श्रीमती जमुना देवी उर्फ बुआ न तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी न ज्यादा चालाक, कहा जाता है कि उन्हें रु, 5 करोड़ भेंट कर सत्र समापन के षड्यंत्रों में विवाद पैदा कर स्थगन और सत्र समाप्ति की घोषणा की जाती थी। अब जबकि विपक्ष नेता अजय सिंह है, उन्हें चाहिए कि किसी भी प्रकार के सत्ताधीशों के विधानसभा समापन के षड्यंत्रों को बेनकाब करते हुए और हर प्रकार के प्रलोभनों से बचते हुए न केवल बजट सत्र को पूरी कालावधि तक चलवाकर सत्ताधीशों के हर भ्रष्टाचार, जन-धन और जनता के शोषण के बारे में खुलकर रखें और बहस कर सत्ताधीशों को सुधरने के लिए बाध्य करें। ताकि जनता इस मुखेरे जानवरों की पार्टी के मु.मं., सभी मंत्रियों और उनके मंत्रालय में चल रही लूट-पाट, छल-कपट, जालसाजियों का यथार्थ सामने आ सकें और स्वयं की छबि एक लड़ाकू नेता के रूप में स्थापित की जा सकें।

म.प्र. वाणिज्य कर कदम-कदम भ्रष्टाचार

सुंदरियों और भ्रष्टों का बोलबाला, मेहनतकशों का मुंह काला

राजस्व वसूली ताक पर सुंदरियों को खुश रखना ज्यादा जरूरी, शैलेन्द्रसिंह की परंपरा का निर्वहन कर रहे आयुक्त अमित राठौर

इंदौर स्थित वाणिज्य कर मुख्यालय को जैसा कि समय माया ने लिखा था कि पीएस और मंत्री के घर से चलाया जाता है, वह वैसे ही सिद्ध होता है कि जिस भ्रष्ट ने जितना पैसा खिलाकर नाकों पर पद चाहा उसे वैसा ही मिला, मुख्यालय पर बैठाये गये डमी आयुक्त की एक नहीं चली, आयुक्त महोदय को गुस्सा भी आया और नाकों पर जाने वाले अधिकांश पदाधिकारियों को डांटा भी, परन्तु बेचारा मंत्री राघवजी का यह अंतिम वर्ष हैं, अगले चुनाव में क्या हो, किसे मालूम। दूसरी ओर राघव की उच्छृंखलता की सीडी जिसकी विदिशा और भोपाल में काफी गर्मी रही ने सिद्ध कर दिया कि इस उमर में भी राघवजी भाई भोग आनंद की कुंठित कामनायें पूरी करने के लिये अपने वित्तमंत्री के पद और गरिमा का भरपूर सदुपयोग उपयोग और घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्व के करायुक्त भ्रष्ट शैलेन्द्र सिंग ने जिस लपटता का परिचय देते हुए चारों तरफ सुंदरियों को बैठाने उन्हें खुश रखने के सारे नियम कानून बलाये ताक रख कर पदोन्नतियां, मनचाही पद स्थापनायें देकर नवाजा वह परंपरा आयुक्त अमित राठौर के कार्यकाल में भी किस तरह निभाई जा रही हैं, उसका उदाहरण देखियेगा कि वृत्त क्र. 11 में सहा.आयुक्त डीएस चौहान को ढाई वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था जहां अरबों रु. प्रति वर्ष का कर संग्रह होता है, बीच शिक्षा सत्र में धकियाकर सहा. आयुक्त रूबी सोनी, जिसके भ्रष्टाचार के चर्चे धार में बहुत सुने जा चुके थे, खुले में उसे पीथमपुर का प्रभार देकर 2 से 10% कमाई करने के लिये करोड़ों रु. के राजस्व को बर्बाद करवा दिया गया। जबकि सहा. आयुक्त डीएस चौहान ने अपने कार्यकाल में 20% ज्यादा राजस्व हर वर्ष बढ़ा कर दिया,

(शेष पेज 7 पर)

400 से ज्यादा स.यं. को 30 वर्ष से पदोन्नतियां नहीं, 1 प्र.अ., 6 मु.अ. को सेवा विस्तार

वोटों की राजनीति से जल संसाधन विभाग ध्वस्त होने की कगार पर

मु.अ., अ.यं., का.यं. को हांक रहे बाबु और उपयंत्री, जनधन की घोर बर्बादी

म.प्र. जल संसाधन विभाग में हाल ही में प्रमुख अभियंता चौबे को और 6 मुख्य अभियंताओं को सेवा निवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया। जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो सरकार को स्पष्ट जवाब देना पड़ा कि योग्य और सक्षम अधिकारियों के अभाव में ऐसा करना सरकार की मजबूरी बन गया था।

दूसरी ओर इसी धूर्त मुख्यमंत्री शिवराज और उसके मुख्य सचिव धूर्त, जालसाज, भ्रष्ट आर परशुराम ने सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं होगा के आदेश को जूते की नोंक पर मारते हुए 22% कुल जमा अजा, अजजा के लिये 60% आरक्षण की व्यवस्था को अपने वोटों की खातिर न केवल बनाये रखा बल्कि धड़ल्ले से उन्हें पदोन्नतियां भी खुलकर और आंख भींचकर दी गई, जिन्होंने सहा.यं.का.यं. रहते हुए खुलकर न केवल स्तरहीन कार्य किये उनके बनाये तालाबों और बांधों में मापदंड के अनुसार न तो गहरा किया गया, न ढंग से बांध बनाये जो पहली दूसरी बरसातों में ही न केवल फूटे वरन् प्राक्कलन में दिये अनुसार उनमें पानी भरा और न ही 50% से ज्यादा सिंचाई की जा सकी, जिन्हें तब भी जालसाज और चालाक भ्रष्ट उपयंत्री व बाबु हांक रहे थे अब मुख्य अभियंता बन जाने के बाद भी वही हांक रहे हैं। ये कहानी इंदौर में बैठे नर्मदा-ताप्ती कछार के मुख्य अभियंता एम एस डाबर की हैं, जिसे एस के पंवार नाम का ये धूर्त बाबू पिछले न केवल 10 वर्षों से हांक रहा है, वर्तमान में इंदौर मु.अ. कार्यालय का अधीक्षक का पदभार भी संभाले हैं, साथ ही धार और इंदौर वृत्त का भी कार्य देख रहा है, ये धूर्त एस.के. पंवार वास्तव में विभागीय सूत्रों के अनुसार शातिर दलाल है, जो अधिकारियों को सुरा-सुंदरियों की सेवायें देकर उन्हें फांसता है, फिर उनके लिये ठेकेदारों से वसूली करना, उपयंत्रियों, सहा. यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों को चमकाना और वसूली कर अपने अधिकारियों को देता है।

धार संभाग में जब वर्तमान मु.अ. डाबर, का.यं. हुआ करता था तब ये एस.के. पंवार न केवल व.ले.लि. बनकर धार संभाग का वरन माही वृत्त में भी वहां के कार्य देखता था और के टी कंस्ट्रक्शन व अन्य ठेकेदारों से मोटी वसूली कर अ.यं. एनएन सिंघल व अन्य अधीक्षण यंत्रियों को भी फांस कर भ्रष्टाचार के धन में वसूली करता था, वर्तमान में यह बाबु एस.के. पंवार रु. 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है और इसका पैसा, इसी के अनुसार रिश्तेदारों के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में लगा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि जल संसाधन विभाग में किस तरह से कार्य हो रहा है।

इस तरफ तो इस विभाग में 90% महिला स्टॉफ चाहे तो किसी भी पद पर हो, कार्यालयों में आराम से 11-12 तक पहुंचती है। फिर 1 बजे से ही इकट्ठी होकर भोजनावकाश में 3 बपजे तक अपने सीटों से गायब रहती हैं। फिर 4.30 बजे से सामान समेट कर जाने की तैयारी शुरू, यही हाल उज्जैन के वृत्त कार्यालय में भी देखा गया, दूसरी तरफ एक बाबु स्तर का एस.के. पंवार दो अधीक्षण यंत्रियों जिसमें धार माही, धार वृत्त और इंदौर वृत्त को हांकने के साथ ही मुख्य अभियंता डाबर का भी पत्ता 1 इंच भी इसके बिना नहीं हिलता। स्वाभाविक इस दलाल को उस स्तर के कार्यों में भ्रष्टाचार सेा वसूली में 5% तक हिस्सा डकारने का हक है।

इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि पूरे मालवा क्षेत्र के दो संभागों यथा इंदौर संभाग के 8 जिलों और उज्जैन संभाग के 6 जिलों कुल 14 जिलों के नर्मदा ताप्ती कछार के जल संसाधन विभाग के 20 संभागों उनके कार्यपालन यंत्रियों, सहा. यंत्रियों की प्रशासनिक व्यवस्थायें और कार्य कैसे चल रहे होंगे, जब इस मु.अ. की डीपीसी की प्रतियां भोपाल स्थित मुख्यालय से सूचना के अधिकार में प्राप्त की, तो मालूम पड़ा कि हर गोपनीय चरित्रावली में इनके हर वरिष्ठ अधिकारी ने इससे मोटा धन हजम कर अच्छी टिप्पणियां की हैं। इनके सारे स्तरहीन कार्यों, प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन अक्षमता को हमेशा नजर अंदाज कर भ्रष्टाचार को महत्व देकर इसे लगातार पदोन्नतियां देकर मुख्य अभियंता बना दिया गया। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये प्रमुख अभियंता बन जायेगा और कोई महाभ्रष्ट सचिव और प्रधान सचिव बैठ गया तो पूरा विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली ही ध्वस्त हो जायेगी, अर्थात चारों तरफ ऐसे ही ढीले, अयोग्य और अक्षम भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला होगा तो कार्य करने वालों को भी भारी असुविधाओं का सामना पूरे प्रदेश में करना पड़ेगा। जैसा कि अभी नर्मदा ताप्ती कछार में हो रहा है। इसके विपरीत सामान्य वर्ग के उच्च शिक्षित और सक्षम 400 से ज्यादा सहायक यंत्रियों को पिछले 30 वर्षों से अभी तक एक भी पदोन्नतियां न देना, वही हाल सामान्य वर्ग के हजारों बाबुओं का भी हैं, जिनमें कई मास्टर्स डिग्रीधारी हैं। सिद्ध करता है कि सत्ताधीश चाहे वो करप्शन ओरियेंटेड नोटोरियस गैंग के कांग्रेसी हो या मुखेरे जानवर पार्टी के भाजपाई, किसी को प्रदेश और इसकी जनता के बेहतर प्रशासनिक भविष्य की नहीं, वरन् वोटों की राजनीति और 22% अजा, अजजा, जनता के हिसाब से 60% आरक्षण देकर उन्हें दबा, डरा-धमकाकर अरबों रु. का धन भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त करने से हैं। वर्तमान में प्रधान सचिव के रुप में बैठे आरएस जुलानिया ने जरूर बहुत ठोस सुधार किये वरना पूरा विभाग डूबने की कगार पर आ चुका था, प्र.स. जुलानिया को चाहिए कि आरक्षित वर्ग को दूसरी पदोन्नतियां तब ही दें जब उनके बराबरी वालों को पदोन्नतियां दे दी जायें। ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है कि आरक्षित वर्ग के 3-3 पदोन्नतियां दे दी जायें, सामान्य वर्ग को एक भी न मिले अन्यथा पदोन्नतियों के लिये सब ही पहले परीक्षायें ली जाये जो सक्षम और योग्य हो उन्हें ही पदोन्नत किया जाये।

अमेरिका कंगाल - 2.70 लाख कर्मचारियों की नौकरी समाप्त

पेज 1 का शेष

उनका उद्देश्य किसी भी आधार पर युद्ध थोप कर सारा पेट्रोल कब्जे में लेना था जो अगले 25-50 वर्षों तक उन्हें मोटा लाभांश दे सके, दूसरी ओर युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन हथियार नं. न केवल स्वयं वरन विश्व के राष्ट्रों को दिखाकर अपने हथियारों की बिक्री के मार्ग को प्रशस्त कर सकें, जिसमें उन कंपनियों द्वारा संचालित संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ ने अपनी आरोप लगाने माहौल बनाने, नाटो राष्ट्रों की सेनायें और नाटो राष्ट्रों के पूंजीपतियों का लाभ दिलाने बहाने धन उपयोग में लाने का बहाना बन सके, अमेरिकी और नाटो सेनाओं ने ईराक पर आक्रमण किया, तेल कुंओं पर कब्जा भी किया, पर युद्ध के लंबे चलने और वहां पर सेनाओं के अरबों डालर के खर्च और कर्ज ने कमर तोड़ दी, इसके साथ ही अमेरिकी पूंजीपतियों का व्यापार के बहाने दूसरे विश्व के राष्ट्रों में अपने शीघ्र और जमा कर मोटा लाभ कमाने के सपनों को भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली, ईराक का खर्च और कर्ज का बोझ उतारने से पहले ही दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान में रहकर ईरान को घेर कर उस पर युद्ध थोपने की उसकी योजना 2004 से थी, पर उसकी हर योजना और षड्यंत्र, उकसाने की कार्यवाही का ईरान ने तो डंटकर मुकाबला किया ही पर शायद यह समय माया को कार्यशैली की अमेरिकी गुंडागर्दी के विरुद्ध 12 वर्ष चलाया जा रहा अभियान भी सफल रहा कि वह ईरान पर हर बार प्रत्यक्ष आक्रमण करने से पीछा हटता रहा, क्योंकि जैसे ही पूरी तैयारी पर आता था, समय माया अपनी साइटों से उसकी हकीकत को व्हाइट हाउसव के ई-मेल पर भेजने के साथ विश्व के मीडिया न्यूज और टीवी चैनल्स पर उसकी बत्तमीजियों पर गालियां के साथ सूचित करता था। इससे न केवल अमेरिकी प्रशासन के वरन् तेल कंपनियों को बदनामी के डर से तो 10 वर्ष बाद भी हमला नहीं कर सका और ईरानी तेल भंडारों पर कब्जा करने के एक तरफ मंसूबे नाकाम रहे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अरबों डालकर के खर्च ने कर्ज बढ़ा दिया। जिसे पूंजपतियों ने अपने हाथ खींच लिये और इस प्रकार अमेरिकी शासन का खजाना खाली होने से उसे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के निदान के विपरीत उल्टे ही अपनी ही सरकार से 2.7 लाख कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करनी पड़ी। अब अधिकतम 3 से 5 महीने में ही लोगों को भुखमरी का शिकार होना ही पड़ेगा। यही कारण अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से केवल अमेरिका रह जायेगा जैसा कि उसके पूंजीपतियों और अमेरिकी शासन ने विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने, विश्व के देशों को व्यापार, पेट्रोल के बहाने लूटने के लिये सोवियत रूस को 27 राज्यों को बांटकर स्वतंत्र राष्ट्र बना दिये थे वैसे ही अमेरिका भी 52 राज्यों को राष्ट्र बनाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र के सत्ताधीशों यथा कांग्रेस और उसका गिरोह इसे अपना मोटा कमीशन डकारने के लिये देशी-विदेशी कं. के इशारे पा कानून बनाकर प्राकृतिक और राज्यों व राष्ट्र के संसाधनों को अंबानी और टाटा व अन्य को सौंपकर जनता का लुटवाने और कंगाल बनाने पर तुले हैं। वह पुनः देश को गुलाम और जनता को पुनः भिखारियों का देश बना देंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803